● वर्ष-3
● अंक-25
रायपुर, गुरुवार
07 सितंबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।
समाचार पचीसा
राजनीति का जनपक्षकार

हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने भारत नाम

राजेश मूणत के बयान ने दिया नई बहस को जन्म

रायपुर। इंडिया बनाम भारत की बहस के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत के ट्वीट ने एक नई बहस को हवा दे दी है। मूणत ने सोशल मीडिया पर भारत नाम का समर्थन करते हुए अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के वकालत की है। मूणत ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक बयान का जवाब देते हुए फेसबुक और ट्विटर हेंडल पर लिखा है कि भारत के प्रति आपके भाव तोड़ने वाले हैं, याद रखिये...भारत अखंड है, सर्वदा विजेता ही है। मूणत ने अपने आगे लिखा है कि हर भारतवासी की मांग है कि अब हर मंच अपने देश को भारत ही कहना ही उपयुक्त रहेगा...भारत हमारे पूर्वजो का दिया नाम है...जबकि भारत की पहचान अंग्रेजो ने इंडिया के तौर पर की थी। मूणत ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए आगे लिखा कि अगर भारत सरकार अपने पूर्वजों के सम्मान में ,अपने देश भारत को गौरवांवित करती है,तो किसी को तकलीफ नहीं बल्कि गर्व होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की स्थापना ही एक अंग्रेज एलन आक्टेवियन ह्यूम ने की थी, आपको अंग्रेजी परंपरा के खत्म होने से दुख तो होगा ही। ..

भारत का हर नागरिक भारतीय हैं..भारत हमारा गर्व है।

इतना ही नहीं मूणत ने आगे लिखा है कि देश मे अंग्रेजी भाषा के स्थान पर हिंदी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मेरा विश्वास है.....शुरुआत हो चुकी है... हिंदी भारत माता के माथे की बिंदी अवश्य बनेगी। मूणत के इस ट्वीट से बहस को बल मिल गया है कि भारत शब्द के साथ ही अब हिंदी भाषा को भी अनिवार्य तौर पर इस्तेमाल किये जाने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा कोई ठोस फैसला लिया जायेगा, हालाँकि इस मुद्दे पर मूणत ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है। लेकिन इस को भाजपा की क्रोनोलॉजी के तौर पर देखा जा सकता है। देश के गृह मंत्री के हाल ही में अपने एक आधिकारिक बयान के राजभाषा पर संसद की समिति की 38वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा था कि भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए इससे बेहतर समय और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक मंचों पर हिंदी और अन्य सभी भारतीय भाषाओं को गर्व के साथ प्रस्तुत करते हैं।

गृह मंत्री ने कहा था कि आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी (क्क्रू स्र्ब्स्र्द्ध) ने देश के सामने पंच प्रण रखे हैं, जिनमें से दो प्रण हैं विरासत का सम्मान और गुलामी के निशान मिटाना। उन्होंने कहा कि इन दोनों प्रण को शत-प्रतिशत लागू करने के लिए सभी भारतीय भाषाओं और राजभाषाओं को अपनी ताकत दिखानी होगी। शाह ने कहा था कि भाषा के सम्मान के बिना विरासत का सम्मान अधूरा है और राजभाषा की स्वीकार्यता तभी मिलेगी जब सभी लोग स्थानीय भाषाओं को सम्मान देंगे। उन्होंने कहा कि राजभाषा के प्रति बिना किसी विरोध के स्वीकार्यता विकसित करने की जरूरत है, भले ही इसकी गति धीमी हो।ज्ञात हो कि दिल्ली में होने वाले जी-20 सम्मेलन में शामिल होने वाले मेहमानों को भोज के लिए आमंत्रित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रिपब्लिक ऑफ इंडिया के स्थान पर रिपब्लिक ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया है, इसके बाद से ही देश में बहस छिड़ी हुई है कि कहीं केंद्र सरकार ने जी 20 सम्मलेन के बाद ही 18-22 सितंबर तक आयोजित होने वाले संसद के विशेष सत्र इंडिया से भारत नाम बदलने को लेकर फैसला,तो नहीं ले लेगी, जो भी हो,फ़िलहाल इस चर्चा ने ह्ष्ठ के परस्पर विरोधी गठबंधन ढ्ढ.ह्.ष्ठ.ढ्ढ.. की नींद उड़ा दी है। मंगलवार को छत्तोसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने के बयान में कहा था कि हमें राष्ट्रपति से निमंत्रण पत्र मिला और अब तक हमें इंडिया के राष्ट्रपति से निमंत्रण पत्र मिलता था, लेकिन यह समय आ गया है भारत के राष्ट्रपति से, इंडिया से इतनी दिक्कत?... अब जब विपक्षी गठबंधन को इंडिया कहा जाता है।

भारत, इंडिया या हिंदुस्तान, सबका मतलब मोहब्बत हैः राहुल

नईदिल्ली। देश में इंडिया बनाम भारत को लेकर एक राजनीतिक विवाद छिड़ा हुआ है। सत्ता पक्ष भारत को लेकर वकालत कर रहा तो विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। इन सब के बीच राहुल गांधी ने भी पूरे मामले को लेकर अपनी राय रखी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत, इंडिया या हिंदुस्तान..., सबका मतलब मोहब्बत है। राहुल गांधी ने 'यूट्यूब' पर अपनी 'भारत जोड़ो यात्रा' से संबंधित वीडियो साझा करते हुए लिखा, '' भारत, इंडिया या हिंदुस्तान..., सबका मतलब मोहब्बत, इरादा सबसे ऊंची उड़ान।'' पूरा मामला तब शुरू हुआ जब जी20 से संबंधित रात्रिभोज के निमंत्रण पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 'प्रेसीडेंट ऑफ भारत' के तौर पर संबोधित किया गया। मंगलवार को इसपर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार देश के दोनों नामों 'इंडिया' और 'भारत' में से 'इंडिया' को बदलना चाहती है। इसमें राहुल गांधी ने पार्टी के कई नेताओं के साथ 4,000 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा की थी और इस दौरान् उन्होंने समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों से बातचीत की थी। यह यात्रा पिछले साल सात सितंबर को कन्याकुमारी से आरंभ हुई थी, जो इस वर्ष 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त हुई थी। यह यात्रा 145 दिन चली थी।

इन दिनों

✍ शिवेंद्र तिवारी

संविधान सभा में बताए थे 'भारत' के मायने

इंडिया बनाम भारत की चर्चा इस वक्त देश में सबसे ज्यादा हो रही है। अब जब चर्चा हो रही है कि क्या आधिकारिक रूप से देश का नाम बदलने वाला है। ऐसे में देश का संविधान लिखने वाली सभा की एक पर हुई बहस के बारे में जानना भी जरूरी होगा। जो बेहद दिलचस्प थी। संविधान का अनुच्छेद एक कहता है इंडिया, यानी भारत, राज्यों का एक संघ होगा। हालांकि, मूल मसौदे में भारत नाम का कोई जिक्र नहीं था। दरअसल, चार नवंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान का मसौदा पेश किया गया था। यह मसौदा डॉ. भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा तैयार किया गया था। लगभग एक साल बाद 17 सितंबर 1949 को अंबेडकर ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें पहले उप खंड में भारत नाम के संशोधन में बदलाव का सुझाव दिया गया। 18 सितंबर 1949 को आजाद देश को एक के बजाय दो नाम देने के प्रस्ताव के बारे में सदस्यों के बीच भारी असहमति देखने को मिली थी। प्रारंभिक प्रावधान पर संविधान सभा में इंडिया और भारत के बीच संबंध पर काफी चर्चा हुई। सदस्यों ने कई संशोधनों का सुझाव दिया लेकिन किसी को भी स्वीकार नहीं किया गया। अंबेडकर के बाद ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता एचवी कामथ ने पहले उप खंड के हिस्से को भारत या अंग्रेजी में इंडिया से बदलने का प्रस्ताव करते हुए पहला संशोधन पेश किया। कामथ यह प्रस्ताव आयरिश संविधान से प्रेरणा लेते हुए सामने लेकर आए थे। इसी चर्चा में कांग्रेस के एक अन्य सदस्य कमलापति त्रिपाठी भी जुड़े। कमलापति ने इस बात पर जोर दिया था कि भारत को इंडिया से अधिक प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कमलापति ने संशोधन प्रस्ताव पर अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। इस दौरान उन्होंने कहा, आज देश के नाम को लेकर एक संशोधन हमारे सामने है, मुझे खुशी होती अगर प्रारूप समिति ने इस संशोधन को किसी अलग रूप में प्रस्तुत किया होता। यदि इंडिया दैट इज भारत के अलावा किसी अन्य अभिव्यक्ति का इस्तेमाल किया गया होता तो मैं सोचता हूं, यह इस देश की प्रतिष्ठा और परंपराओं के अधिक अनुरूप होता और वास्तव में इससे इस संविधान सभा का भी अधिक सम्मान होता। यदि दैट इज शब्द आवश्यक होते तो, जो प्रस्ताव हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है उसमें भारत दैट इज इंडिया शब्द का प्रयोग करना अधिक उचित होता। मेरे मित्र कामथ ने यह संशोधन पेश किया है कि %भारत जैसा कि इसे अंग्रेजी भाषा में इंडिया कहा जाता है का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रारूप समिति ने इसे स्वीकार कर लिया था यदि वह अब भी इसे स्वीकार करती है तो यह हमारी भावनाओं और हमारे देश की प्रतिष्ठा के प्रति सराहनीय विचार होगा। हमें इसे स्वीकार करने में बहुत खुशी होती।

गणेश चतुर्थी से नए संसद भवन में बैठेंगे सांसद

नईदिल्ली। संसद के विशेष सत्र का पहला दिन 18 सितंबर को पुरानी इमारत में आयोजित किया जाएगा। सत्र 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर नई इमारत में स्थानांतरित किया जाएगा। पांच दिवसीय विशेष सत्र में कथित तौर पर महिला आरक्षण और %एक राष्ट्र-एक चुनाव% पर विधेयक पेश किया जाएगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का पांच दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। सत्र का एजेंडा जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया। पूजा के साथ शुरू हुए उद्घाटन समारोह के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रधानमंत्री के साथ थे। उसी दिन स्पीकर की कुर्सी के पास ऐतिहासिक सेन्गोल स्थापित किया गया था।

जारी है राजनीति

संसद के विशेष सत्र को लेकर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था। अपने पत्र में उन्होंने 9 मुद्दों को उठाया था। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने बुधवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बताया कि विशेष संसद सत्र के लिए कोई एजेंडा सूचीबद्ध नहीं किया गया था और इस दौरान चर्चा के लिए मणिपुर में हिंसा और मूल्य वृद्धि सहित नौ मुद्दों को उठाया गया था। गांधी द्वारा सूचीबद्ध मुद्दों में केंद्र-राज्य संबंध, सांप्रदायिक तनाव के मामलों में वृद्धि, चीन द्वारा सीमा उल्लंघन और कई खुलासों के आलोक में अदानी व्यापार समूह के लेनदेन की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की मांग शामिल है।

पुरानी संसद से शुरू होगा विशेष सत्र

सरकार का जवाब

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने पत्र का जवाब देते हुए कहा कि वह (सोनिया गांधी) राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं...अतीत में कहीं भी सत्र बुलाने से पहले विपक्षी दलों से सलाह-मशविरा नहीं किया गया...यह सरकार का विशेषाधिकार है। गांधी को संबोधित एक पत्र में उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह हमारे लोकतंत्र के मंदिर संसद के कामकाज का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही हैं और जहां कुछ भी नहीं है वहां अनावश्यक विवाद पैदा कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है जिस पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने जवाब भेजा है...यह दुखद है कि सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की है...मैं सोनिया गांधी और उनकी पार्टी से विशेष सत्र में हिस्सा लेने का आग्रह करता हूं...कांग्रेस के पास कोई विषय नहीं हैं...वे केवल देश को बांटने वाले बयान देते हैं।

जिले मे चल रहे मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप कार्यक्रम के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं स्वीप नोडल अधिकारी प्रेमप्रकाश शर्मा के निर्देशन एवं संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीमा ठाकुर के मार्गदर्शन में कोण्डागांव विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनियागांव के लगभग 500 छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम संयोजक टी.ऐंकट राव के नेतृत्व में एक विशाल एवं आकर्षक मानव श्रृंखला बनाकर छात्र छात्राओं ने वोटर लिस्ट में नाम लिखाने हेतु प्रेरित करने के लिए वोटर कार्ड बनाएं, घर घर अलख जगाएंगे।

प्रमुख समाचार

मोदी बोले, उदयनिधि के बयान पर सही से जवाब देना चाहिए

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद सनातन धर्म टिप्पणी का उचित जवाब दिया जाना चाहिए। वह मंत्रिपरिषद में बोल रहे थे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास में न जाएं, बल्कि संविधान के अनुसार तथ्यों पर कायम रहें। साथ ही मुद्दे की समसामयिक स्थिति पर भी बात करें। प्रधान मंत्री ने मंत्रियों को इंडिया बनाम भारत विवाद पर टिप्पणी न करने की भी सलाह दी, और कहा कि केवल अधिकृत व्यक्ति को ही इस मामले पर बोलना चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से करने के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। शनिवार को चेन्नई में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा, ऐसी चीजों का विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि नष्ट किया जाना चाहिए। इस टिप्पणी पर कई राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, भाजपा ने कांग्रेस पर उनकी टिप्पणी की निंदा करने पर जोर दिया। हालाँकि, बाद में उन्होंने दावा किया।

जी20 में आ रहे मेहमानों को होंगे सनातन संस्कृति के दर्शन

नईदिल्ली। जी20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत की राजधानी दिल्ली में मेहमानों का जमावड़ा लगने वाला है। दिल्ली में मेहमानों के स्वागत के लिए कई तैयारियां की गई है। दिल्ली की सड़ों का कायाकल्प किया गया है जिसके जरिए मेहमानों को भारत की सनातन, सांस्कृतिक विरासत, कला और विकास के पथ के दर्शन कराए जाएंगे। इसके साथ ही भारत पूरी तरह से तैयार है कि विदेशी प्रतिनिधियों के समक्ष अपनी डिजिटल ताकत को प्रदर्शित करे। राजधानी के प्रगति मैदान में नवनिर्मित सम्मेलन स्थल 'भारत मंडपम' में नौ एवं 10 सितंबर को जी20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में शामिल होने के लिए आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए समूचे नयी दिल्ली क्षेत्र को विशेष रूप से सजाया-संवारा गया है। दिल्ली की सड़कों पर हर तरफ वॉल पेंटिंग्स बनाई गई है, जहां से डेलीगेट्स के काफीलों को गुजरना है। ये कलाकृतियां भैरो मार्ग रेलवे ब्रिज के नीचे दीवारों पर बनाई गई है। इसमें रामायण, महाभारत और विष्णु अवतार के भव्य रूप को दर्शाया गया है।

पाक जिंदाबाद का नारा लगाने वाले नेता ने कर दिया खेल

नईदिल्ली। पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले और पाकिस्तान के हमदर्द के रूप में विख्यात नेशनल कांफ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन को सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते और देश की संप्रभुता को स्वीकार करते हुए एक हलफनामा दाखिल करने को कहा था। लेकिन मंगलवार को मोहम्मद अकबर लोन ने उच्चतम न्यायालय में जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें लोकसभा सदस्य के तौर पर ली गयी अपनी शपथ को दोहराते हुए कहा है कि वह संविधान का संरक्षण और देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेंगे। उनके इस शपथ पत्र से नाराज केंद्र ने दावा किया कि यह राष्ट्र का अपमान है। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि मोहम्मद अकबर लोन के हलफनामे में यह पढ़ा जाना चाहिए था...''कि मैं आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधि का समर्थन नहीं करता।'' तुषार मेहता ने कहा, ''यह (हलफनामा) राष्ट्र का अपमान करने जैसा है।''

जब तक समाज में भेदभाव है, आरक्षण रहना चाहिएः भागवत

नागपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने बुधवार को आरक्षण पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में भेदभाव है, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भेदभाव भले ही नजर नहीं आए, लेकिन यह समाज में है। उन्होंने कहा कि सामाजिक व्यवस्था में हमने अपने बंधुओं को पीछे छोड़ दिया। हमने उनकी देखभाल नहीं की और यह 2000 सालों तक चला। इसलिए आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए, जब तक ऐसा भेदभाव बना हुआ है। संविधान में प्रदत्त आरक्षण का हम संघवाले पूरा समर्थन करते हैं। सरसंघचालक ने कहा कि यह केवल वित्तीय या राजनीतिक समानता सुनिश्चित करने के लिए नहीं, बल्कि सम्मान देने के लिए भी है। उन्होंने कहा कि भेदभाव झेलने वाले समाज के कुछ वर्गों ने 2000 सालों तक यदि परेशानियां उठाईं तो क्या हम हम और 200 साल कुछ दिक्कतें नहीं उठा सकते? उन्होंने अखंड भारत पर कहा कि जो लोग भारत से अलग हो गए।

खालिस्तान समर्थक एक्टिविटी पर ऋषि सुनक की दो टूक

नईदिल्ली। ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक तत्वों की गतिविधियों पर भारत की चिंताओं का समर्थन करते हुए, ब्रिटिश प्रधान मंत्री ऋषि सुनक ने बुधवार को कहा कि उग्रवाद का कोई भी रूप स्वीकार्य नहीं है, उन्होंने कहा कि वैध विरोध करने का अधिकार हिंसक या धमकी भरे व्यवहार तक नहीं है। एक विशेष साक्षात्कार में सुनक ने कहा कि वह हिंसक, विभाजनकारी विचारधाराओं को बाधित करने और उनका मुकाबला करने के सरकार के कर्तव्य को बहुत गंभीरता से लेते हैं। ब्रिटेन खालिस्तान समर्थक उग्रवाद के खतरे से निपटने के लिए भारत सरकार में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। ब्रिटेन में खालिस्तानी समर्थक तत्वों की गतिविधियों को लेकर भारत में चिंताएं बढ़ गई हैं, खासकर मार्च में लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले के बाद। सुनक की टिप्पणी जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आने से कुछ दिन पहले आई है। ब्रिटेन में उग्रवाद का कोई भी रूप स्वीकार्य नहीं है और मैं हिंसक, विभाजनकारी विचारधाराओं को बाधित करने और उनका मुकाबला करने की सरकार की जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लेता हूं, चाहे वे कुछ भी हों।

चुनाव में जिस खर्च की दुहाई दी जा रही है, वह भ्रष्ट राजनीति की वजह से है

अनिल सिन्हा

केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। जाहिर है, इससे राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। विपक्ष इसे प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता में बने रहने की राजनीतिक कोशिशों के रूप में देख रहा है। यह भी पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री लोकसभा चुनावों के नजदीक आने पर ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। यह राय उन्होंने 2018 में भी व्यक्त की थी, उसके बाद भी इसे दोहराया था, लेकिन तब इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया था। सवाल उठता है कि क्या इस बदलाव के लिए यह सही समय है? आशंकाओं को किनारे रख दिया जाए तो भी 'एक देश, एक चुनाव' के सिद्धांत पर अमल के लिए इस साल के आखिर में हो रहे कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव टालने पड़ेंगे और उन विधानसभाओं के कार्यकाल बढ़ाने होंगे। या 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव निश्चित समय से पहले कराने होंगे।

इससे भी बात पूरी तरह से नहीं बनेगी। विधानसभाओं के कार्यकाल अलग-अलग हैं और इनके साथ लोकसभा चुनाव कराने के लिए राज्यों की सरकारें बर्खास्त करनी होंगी या उनसे त्यागपत्र दिलाने होंगे और विधानसभाओं को भंग करना होगा। बीजेपी शासित राज्यों में यह आसानी से हो सकता है, लेकिन विपक्ष-शासित राज्यों में ऐसा करने के लिए धारा 356 का उपयोग करना होगा और राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। जाहिर है, यह पूरी कसरत केंद्र सरकार के लिए आसान नहीं साबित होने वाली। सत्ता पक्ष ने 'एक देश, एक चुनाव' के पक्ष में चुनावी खर्च को छोड़कर कोई दूसरा बड़ा तर्क नहीं दिया है। इस चुनावी खर्च में मानव संसाधनों का वह सारा खर्च शामिल है, जो प्रशासनिक तंत्र के जरिए चुनावों में लगाए जाते हैं। एक और तर्क यह है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण विकास कार्य रुक जाते हैं। लेकिन यह अर्धसत्य पर आधारित है। आचार संहिता में सिर्फ नीतिगत फैसले लेने की मनाही है। चालू परियोजनाओं और कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने को लेकर कोई बंधन नहीं है।

चुनाव खर्च और प्रशासनिक तंत्र के इस्तेमाल का सवाल उठाते वक्त राजनेता भूल जाते हैं कि बेहताशा खर्च के लिए चुनाव का बार-बार होना होना उतना जिम्मेदार नहीं है, जितना राजनीति का लगातार भ्रष्ट और हिंसक होते जाना है। चुनाव में अधिक पुलिस बल या बड़े प्रशासनिक तंत्र की जरूरत इसलिए पड़ती है कि राजनीतिक दल सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। राजनीति में अपराधियों और कालाधन रखने वालों की हिस्सेदारी बढ़ने के कारण चुनावों पर सरकारी खर्च उसी अनुपात में बढ़ा है। जहां तक गैर-सरकारी खर्च का सवाल है तो वोट के लिए शराब पिलाने, कपड़ा और पैसा बांटने की संस्कृति चुनावी राजनीति का अभिन्न हिस्सा हो चुकी है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिलने वाले चंदा इतना अपारदर्शी है कि यह पता ही नहीं चलता, किसका धन कौन सी पार्टी इस्तेमाल कर रही है। सबसे बड़ा मसला है पांच साल के लिए प्रतिनिधि चुनने से भारत की संसदीय प्रणाली और इसके संघीय ढांचे को होने वाले नुकसान का। भारत की संविधानसभा ने बहुत चर्चा के बाद राष्ट्रपति प्रणाली को खारिज कर दिया था जिसके तहत पूरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति और विधायिका के सदस्यों को चुना जाता है।संसदीय प्रणाली में सदन में किसी को भी बहुमत नहीं मिलने पर फिर से चुनाव कराना आवश्यक होता है। इस प्रणाली का मूल तत्व है कि जब सरकार बहुमत का विश्वास खो दे तो जनता के पास जाया जाए। देश की विविधता और अलग-अलग राज्यों और समुदायों को सत्ता में भागीदार बनाने के लिहाज से इस प्रणाली को संविधानसभा ने सही माना। इस प्रणाली के कारण विविधताओं वाले इस देश में बहुसंख्यकवाद को कमजोर किया गया है। पांच साल के बीच चुनाव नहीं कराने की पाबंदी का मतलब है कि बहुमत खो देने वाली सरकार बनी रहे और केंद्र सरकार धारा 356 के तहत राज्यों का शासन चलाए।यह संघीय ढांचे के लिए कितना नुकासानदेह है, इसे सरकारिया कमिशन की सिफारिशों में देखा जा सकता है। दल-बदल के जरिए जिस तरह सरकारें बदली जाती हैं उससे जनता के पास इन सरकारों को हर हाल में बर्दाश्त करने के अलावा कोई उपाय ही नहीं रहेगा। लोकसभा को पूरे पांच साल तक बनाए रखने का तर्क इस लिहाज से भी आपत्तिजनक है।

भारत जोड़ो यात्रा ने बदली राजनीति की दिशा : विक्रम मंडावी

बीजापुर। बीजापुर में स्थानीय विधायक व भारत जोड़ो यात्रा के जिला प्रभारी विक्रम मंडावी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर आगामी सात सितंबर को ज़िला मुख्यालय बीजापुर में होने वाली भारत जोड़ो पद यात्रा की जानकारी दी है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विक्रम मंडावी ने कहा कि हम सब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सात सितंबर को वर्षगांठ मनायेंगे। विधायक ने कहा कि देश के वर्तमान हालात में जब क्षेत्रियता, धर्म, सांप्रदायिकता के नाम पर देश की सत्ता में बैठे हुए लोग राजनीति कर रहे है। ऐसे में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा देश के लोगों के सामने एक नई उम्मीद लेकर सामने आई थी।

विधायक विक्रम ने कहा कि जब देश चलाने वाला दल आम आदमी की जरूरतों, शिक्षा, रोजगार को पीछे धकेल कर धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे है। तब उस समय कांग्रेस जैसी जन सरोकार वाली पार्टी का यह नैतिक और राजनैतिक कर्तव्य हो जाता है कि वह देश को बचाने देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिये भारत जोड़ो जैसा महाअभियान चलाये और भारत जोडो यात्रा का यही उद्देश्य था

विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि पिछले साल सात सितंबर 2022 को राहुल गांधी ने ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी जो भारत के किसी भी राजनेता द्वारा अब तक की सबसे लंबी पदयात्रा है। लाखों लोग प्रेम और एकता के साथ धर्म, समुदाय, जाति आदि की परवाह किए बिना हर भारतीय को एकजुट करने की राहुल की अटूट भावना से मंत्रमुग्ध थे। उनकी यह विचारशील पहल समय की मांग थी, जिसने मूल रूप से हमारे देश में राजनीति की दिशा बदल दी। विशेष रूप से यात्रा के बाद कर्नाटक का चुनाव परिणाम, कांग्रेस पार्टी को सत्ता में वापस लाने की लोगों की सामूहिक इच्छा की एक उत्कृष्ट अभिव्यक्ति थी।

विधायक विक्रम ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोडो यात्रा से देश के आम आदमी की समस्याओं को आवाज दिया है। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, सामाजिक वैमनस्यता के खिलाफ देश की जनता में जनजागरण पैदा किया। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत के जनमन में रच बस गयी है। सारा भारत अपनी तकलीफों के निदान को लेकर एकजुट हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा से देश के लोगो मे उम्मीद की नई किरण पैदा हुई है। राहुल गांधी प्रेम उम्मीद और सदभावना के नये बीज बोते चल रहे थे।

अवैध अतिक्रमण करने वाले ग्रामीणों को किया गया गिरफ्तार

कबीरधाम। कबीरधाम जिले के कवर्धा वनमंडल अंतर्गत भोरमदेव अभ्यारण्य चिल्फी परिक्षेत्र के ग्राम कुमान और नंदिनी से लगे वन भूमि कक्ष क्रमांक पीएफ 170 में ग्राम कुमान एवं नंदिनी के ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण के उद्देश्य से अवैध रूप से साफ-सफाई, कटाई करने पर सात आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वन विभाग के डीएफओ चूड़ामणि सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार परिसर रक्षक एवं परिक्षेत्र सहायक द्वारा समझाईश दिया गया और मना किया गया। लेकिन ग्रामीण नहीं माने और विवाद करते हुए कटाई सफाई जारी रखा।

कर्मचारियों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में सूचित किया गया। अधीक्षक भोरमदेव अभ्यारण्य, परिक्षेत्र अधिकारी चिल्फी, वन कर्मियों एवं पुलिस बल लेकर मौका स्थल गए और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया गया। लेकिन समझाने के बाद भी उनके द्वारा यह कार्य नहीं रोका गया और उग्र होकर विवाद करने लगे तथा पुन: कटाई सफाई करने लगे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मुख्य वन संरक्षक दुर्ग, वन मंडलाधिकारी कवर्धा भी मौका स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश दिया गया लेकिन इसके बाद भी सहयोग करने के लिए तैयार नही हुए और कुल्हाड़ी लेकर नारेबाजी किए। इसके बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया।

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इन ग्रामीणों द्वारा भोरमदेव अभ्यारण्य क्षेत्र के वन क्षेत्र के वृहत भू-भाग लगभग 35 हेक्टेयर की सफाई कर चुके हैं, जिसमे असंख्य लताओं बेलाओ, झाड़ियों, औषधीय पौधों, वृक्षों को काटा गया है। ऐसा करते हुए उनके द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अभ्यारण्य क्षेत्र में बिना अनुमति प्रवेश, विनिर्दिष्ट वृक्षों पौधों की साफ सफाई कराई, हथियार के साथ अभ्यारण्य में प्रवेश, वन्य प्राणियों के प्राकृतिक रहवास को नष्ट करना, अपराध के लिए उकसाना आदि प्रकार के अपराध किए गए हैं। सात आरोपियों को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय कवर्धा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता का पालन सुनिश्चित करें : सांसद मंडावी

कांकेर। लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री मोहन मंडावी की अध्यक्षता में आज जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें केन्द्रीय, राज्य एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों में विभागीय प्रगति की समीक्षा किया गया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। लोक निर्माण विभाग तथा प्रधानमंत्री सड़क योजना द्वारा किये जा रहे सड़कों के निर्माण की समीक्षा करते हुए सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता का पालन सुनिश्चित करते हुए समय पर पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया।

मलाजकुडुम से आमाबेड़ा मार्ग के प्रगति की समीक्षा भी की गई, विभागीय अधिकारी द्वारा उक्त सड़क के निर्माण कार्य दिसम्बर तक पूरा होना बताया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर माकड़ी के पास चिनार नदी में पुल निर्माण कार्य के संबंध में जानकारी लिया गया तथा अस्थाई पुल (रपटा) को भी मजबूत बनाने के निर्देष दिये गये, ताकि वाहनों का आवाजाही उक्त रपटा से हो सके। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हैण्डपंप मैकेनिकों का मजदूरी भुगतान अविलंब करने के लिए भी निर्देषित किया गया। जिले के सभी छात्रावास-आश्रमों को गौठानों से मैपिंग करने के निर्देष दिये गये, ताकि गौठानों से छात्रावास-आश्रम एवं स्कूली बच्चों को ताजी हरी सब्जी उपलब्ध कराया जा सके। जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी निर्देषित किया गया।

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत मंडल, जल संसाधन, षिक्षा विभाग, कृषि एवं उद्यानिकी, महिला बाल विकास विभाग सहित अन्य विभागों में संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों में प्रगति की समीक्षा किया गया। बताया गया कि मनरेगा के अंतर्गत जिले को 43 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके विरूद्ध अब तक लगभग 28 लाख मानव दिवस सृजित किया जा चुका है। जिले में 128 बीसी सखी कार्य कर रहे हैं, जिनके माध्यम से लगभग 02 करोड 50 लाख रूपये का भुगतान विभिन्न हितग्राहियों को किया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण अंतर्गत वर्ष 2016 से 2019 तक 18 हजार 580 आवास स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से अधिकांश पूर्ण हो चुके हैं। वर्ष 2020 से अब तक 10 हजार 631 आवास स्वीकृत किये गये हैं जो प्रगतिरत है।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि पूरे छत्तीसगढ़ में कांकेर जिले में सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड जारी किये गये हैं तथा 01 लाख 29 हजार लोगों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लगभग 85 करोड़ रूपये के नि:षुल्क ईलाज की सुविधा प्राप्त हुई है। शासकीय कोमलदेव जिला चिकित्सालय कांकेर में एमआरआई मषीन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चारामा में अब सोनोग्राफी तथा सिजेरियन की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। षिक्षा विभाग की समीक्षा में बताया गया कि कक्षा पहली से 10वीं तक अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को नि:षुल्क पाठ्य पुस्तक तथा कक्षा पहली से 8वीं तक अध्ययनरत बच्चों को दो जोड़ी गणवेष नि:षुल्क उपलब्ध कराया गया है।

सीएम के खिलाफ टिप्पणी करने का मामला

सीएमएचओ ने कुक अंजली साहू को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

बालोद। बालोद जिले में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी द्वारा मुख्यमंत्री के नाम से अभद्र टिप्पणी करते हुए बनाए गए कविता का वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने शक्ति दिखाई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभाग के जिला अस्पताल में कुक के पद पर पदस्थ अंजलि साहू को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। वहीं नोटिस के जवाब के बाद विधिवत कार्रवाई करने की बात जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कही गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मानव संसाधन नीति के तहत पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस महिला के मुख्यमंत्री के खिलाफ बनाए गए कविता के वीडियो को भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी शेयर किया था।

स्वास्थ्य विभाग में कुक के रूप में पदस्थ इस महिला द्वारा मुख्यमंत्री को हिंदुस्तान का सबसे झूठा नेता बताया गया है और नियमितीकरण की बात को लेकर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा गया है। वीडियो के वायरल होने के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी ने इससे काफी शेयर किया वहीं विभाग ने इसे गंभीरता से लिया और नोटिस भी जारी कर दिया है।

कुक अंजलि साहू के द्वारा कविता में सोशल मीडिया पर वायरल हुए विडियो में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए शासन के खिलाफ टीका टिप्पणी किया गया है जो सिविल सेवा अधिनियम 1965 के नियम के तहत घोर उलंघन के श्रेणी में आता है। उक्त पत्र में सीएमएचओ ने उल्लेख किया है कि आपके द्वारा की गई टीका- टिप्पणी अनुशासनात्मक श्रेणी में आता है। पत्र मिलने के बाद जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है।

शिक्षक वास्तविक जीवन के मूल्यों के भी ज्ञाता : रंजना साहू

■ **उच्च संस्कारों को परिलक्षित करते हुए शिक्षक दिवस पर अपने शिक्षकों से आशीर्वाद लेने पहुंची विधायक**

धमतरी। शिक्षक दिवस के दिन अपने गुरु के प्रति भाव प्रकट कर उनके प्रति आदर व्यक्त करने का ऐसा पर्व है जिसे समूचे देश में मनाने की परंपरा है,देश के पहले उपराष्ट्रपति महान शिक्षाविद भारत रत्न डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को समर्पित इस दिन की अपनी विशेष महत्ता है,इसी पर्व पर धमतरी विधायक रंजना साहू ने गुरु शिष्य की परंपरा का अनुसरण करते हुए अपने गुरुजन शासकीय महाविद्यालय के सेवानिवृत प्राचार्य डॉ अनंत दीक्षित सर जी, गर्ल्स स्कूल के सेवानिवृत प्राचार्य एच एल सिन्हा सर जी एवं महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक श्रीमती चंद्रिका साहू जी से उनके निवास पहुंच भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया,अपने गुरुजनों का कुशलक्षेम जानकर विभिन्न विषयों में गुरुजनों से विधायक ने मार्गदर्शन लिए। विधायक ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र के निर्माता होते हैं, जोकि ज्ञानदीप से विद्यार्थियों का जीवन प्रकाशित करता है, यह दिन हमारे शिक्षकों को समर्पित है, उन गुरुओं को जिन्होंने हमें ज्ञान, समझ और आत्म-समर्पण की सीख दिए,शिक्षक न केवल पाठग्रंथों के ज्ञाता होते हैं,बल्कि वास्तविक जीवन के मूल्यों के भी ज्ञाता होते हैं। शिक्षक वो मार्गदर्शक होते हैं, जो हमें सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, शिक्षक न सिर्फ पढ़ाते है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को सीखते हैं। श्रीमती साहू ने कहा कि एक कहावत है गुरु बिना जीवन अंधकार के समान होता है यह कहावत सत्य है, क्योंकि इस संसार में जीवन को सही राह दिखाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, उनके बिना जीवन निराधार होता है, मैं उन सभी गुरुचरणों को वंदन करती हूं जिन्होंने मुझे सही राह दिखाकर आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किए।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

जनहानि तथा पशुधन हानि को रोकने जिपं सीईओ ने किया जागरूकता रथ को रवाना

कोरबा। जिला पंचायत परिसर में मंगलवार को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री विश्वदीप एवं नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने हरी झण्डी दिखाकर 'स्ट्रे कैटल रिस्पांस फोर्स जागरूकता' रथ को रवाना किया। यह जागरूकता रथ जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मुख्य मार्गों का भ्रमण करते हुए आमजनों को जागरूक करने का कार्य करेगा। जिले के मुख्य मार्गों एवं सड़कों पर आवारा पशुओं के अनावश्यक रूप से विचरण करने पर दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है जिससे जनहानि तथा पशुधन हानि भी हो जाती है। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आज जागरूकता रथ को रवाना किया गया। इस जागरूकता रथ का उद्देश्य पशुपालकों को अपने पशुओं को घर में बांधकर रखने तथा पशु एवं जन-धन हानि रोकने के लिए आम जनता को जागरूक करना है। जागरूकता रथ के माध्यम से पशुपालकों एवं आमजनता से जनहानि एवं पशुहानि रोकने के लिए अपील की जा रही है।

आदिवासी समाज के लोगों ने वनविभाग का किया घेराव

गरियाबंद। अतिक्रमण के आरोप में वन विभाग द्वारा पकड़े गए एक आदिवासी की मौत के बाद भड़के समाज के लोगों ने वन विभाग का घेराव करते हुए चक्काजाम कर दिया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के समझाईश के बाद किसी तरह विरोध-प्रदर्शन बंद हुआ। विदित हो कि विगत 28 अगस्त को गरियाबंद वन मंडल ने गरियाबंद रेंज के झीतरीडूमर निवासी भोजराम को अतिक्रमण के आरोप में पकड़ा था। आरोपी को गरियाबंद उप जेल में दाखिल कराया गया था, यहां जेल पहुंचने के बाद दूसरे दिन की उसकी तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गई। जेल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे रायपुर रेफर कर दिया गया था। यहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस बात को लेकर आदिवासी समाज में भयंकर आक्रोश था। इसी के चलते आदिवासियों ने एकजुट होकर गरियाबंद वन विभाग का घेराव कर दिया। नाराज समाज के लोगों ने तिरंगा चौक् में जमा होकर नेशनल हाईवे को पूरी तरह से अवरूद्ध कर जमकर नारेबाजी की।

वरिष्ठ अधिकारियों की मनमानी से आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे प्राइवेट स्कूल के संचालक

नगरी। सरकारी उपेक्षाओं से त्रस्त प्राइवेट स्कूल के संचालकों ने शिक्षक दिवस के अवसर में शिक्षक दिवस नहीं मानने और शाला में अवकाश रखने का निर्णय लिया एवं विरोध स्वरूप सभी संचालकों ने काला फीता बांधकर विरोध दर्ज किया। आपको बता दें की मंगलवार को अपराह्न 3:00 बजे सभी निजी संस्थाओं के संचालकों ने प्रेस वार्ता कर अपनी समस्याओं व कार्यों को स्पष्ट करते हुए बताया की प्रमुख कारण आरटीई के शिक्षण शुल्क का विगत 3 वर्षों से भुगतान नहीं मिलने के कारण संस्था संचालकों को गंभीर आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है इसके वजह से संस्था संचालन की व्यवस्था व्यवस्था चरमरा रही है। राशि की भुगतान के लिए उच्च स्तर पर गुहार लगाई जा चुकी है लेकिन विगत 6 माह से राशि भुगतान का सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, तथा बार-बार जिला शिक्षा कार्यालय धमतरी व शिक्षा विभाग संचनालय रायपुर बुलाकर सभी संचालकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।

पाटन, कवर्धा सहित चार नगरों के मास्टर प्लान लागू

दुर्ग। आवास एवं पर्यावरण विभाग ने पाटन, कवर्धा, धमतरी एवं पिथौरा निवेश क्षेत्रों हेतु मास्टर प्लान 2031 की अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग ने पिछले महीने ही रायपुर एवं कुरूद का मास्टर प्लान भी जारी किया था। नए मास्टर प्लान में पाटन मास्टर प्लान 2031 महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र है। पाटन मास्टर प्लान 2031 लगभग 1 लाख की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। नियोजन दृष्टिकोण से सेवा सुविधाओं की क्षमता विकास योजना कार्यकाल के आगे की अवधि के लिए भी प्रस्तावित की गई है। इसके साथ-साथ सुनियोजित विकास एवं यातायात की सुगमता हेतु विभिन्न प्रस्ताव दिए गए हैं। कवर्धा मास्टर प्लान 2031 एवं पिथौरा मास्टर प्लान 2031 भी 1 लाख की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए है, जबकि धमतरी विकास योजना 2031 ढाई लाख जनसंख्या की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 17.49 लाख रूपये स्वीकृत

कांकेर। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका में निहित निर्देशों एवं प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ के विधायक श्री अनूप नाग की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा कोयलीबेड़ा विकासखंड अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 17 लाख 49 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किया गया है। कोयलीबेड़ा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत छोटेकापसी बाजार स्थल पर सी.सी. रोड निर्माण के लिए 05 लाख 20 हजार रूपये, ग्राम पंचायत बलरामपुर अम्बेडकर चौक में रंगमंच निर्माण हेतु 03 लाख रूपये, ग्राम पंचायत मरोड़ा के पी.व्ही. 75 से हनुमान चट्टान मार्ग में 600 एम.एम. व्यास हयुम पाईप 02 नग पुलिया निर्माण के लिए 01 लाख 50 हजार रुपये, श्यामनगर पी.व्ही. 13 में रंगमंच निर्माण हेतु 03 लाख रुपये और विवेकानंदनगर पी.व्ही. 05 में मुक्तिधाम निर्माण के लिए 04 लाख 79 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत राशि हेतु कोयलीबेड़ा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है।

सरकार का नीतिगत फैसला, नहीं कर सकते हस्तक्षेप : हाईकोर्ट

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए संशोधन को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका में कहा है कि यह वैध है क्योंकि यह सरकार का नीतिगत निर्णय है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

दरअसल छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा जारी शिक्षक की भर्ती के लिए दिनांक 04.05.2023 की अधिसूचना और विज्ञापन को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। जारी अधिसूचना को चुनौती देने का मुख्य आधार शिक्षक के संबंधित विषयवार पद के लिए आवश्यक विषयवार स्नातक की डिग्री को गायब करना है। अधिसूचना के अनुसार, संस्कृत में स्नातक उम्मीदवार किसी स्कूल में गणित पढ़ा सकता है और इसके विपरीत अधिसूचना को इस आधार पर भी चुनौती दी गई कि केवल विधायी संशोधन के

माध्यम से 2019 के नियमों में आवश्यक संशोधन लाया जा सकता है। विभागीय अधिसूचना और कैबिनेट नोट विधायी अधिनियम को खत्म नहीं कर सकते।

इस मामले में याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अधिसूचना और विज्ञापन प्रारंभिक वर्षों में राज्य में शिक्षा के मानक को कम कर रहे हैं। बाल शिक्षा जो बाल विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्षम शिक्षक उन्हें सौंपा गया विषय पढ़ाएगा। अधिसूचना से शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आएगी। यह अधिसूचना शिक्षा के अधिकार अधिनियम का भी उल्लंघन है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता किया गया है।

यह भी तर्क दिया गया कि नियमों में संशोधन केवल विधान सभा द्वारा किया जा सकता है और विभाग की अधिसूचना या कैबिनेट भर्ती नियम 2019 में संशोधन नहीं कर सकती है,यह संशोधन राज्य और केंद्र के शिक्षा नियम के लक्ष्य और उद्देश्य के अनुरूप नहीं है। यह बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। दलीलों पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और याचिका के साथ दायर स्थगन आवेदन पर भी नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चार सप्ताह के भीतर याचिका का जवाब दाखिल करना होगा और स्थगन आवेदन देना होगा।

कांग्रेस सनातन के दुश्मनों के साथ है या खिलाफ अपनी स्थिति स्पष्ट कर : शशि पवार

धमतरी। भारतीय जनता पार्टी धमतरी के द्वारा मंगलवार को गांधी चौक मैदान में डीएमके के मंत्री उदय निधि द्वारा सनातन धर्म के लिए अपमानजनक बातें बोलने के विरोध में पुतला दहन किया गया एवं उदयनिधि के इस कृत्य के विरोध में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गयी । जिलाध्यक्ष ठाकुर शशि पवार ने कहा कि डीएमके के उदय निधि इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं, उन्होंने यह बयान मुंबई की बैठक खत्म होने के 24 घंटे के अंदर दिया । इंडिया गठबंधन का यही एजेंडा तय हुआ है कि सनातन धर्म और हिंदुओं का अपमान करना है । उदय निधि ने सनातन और हिंदू धर्म की तुलना मलेरिया ,डेंगू ,वायरस, कोरोना से की, और उसके उन्मूलन की बात की। उदय निधि के इस बयान का समर्थन कार्ति चिदंबरम और और दक्षिण के कांग्रेस

के अन्य नेताओं ने भी किया है, कांग्रेस हमेशा हिंदू और सनातन धर्म का अपमान करती रही है उदय निधि के इस बयान पर, सनातन धर्म के अपमान पर पूरा देश और हिंदू समाज और पूरे देश के सनातनी बहुत आहत है। श्री पवार ने कहा कि कांग्रेस को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिये कि वो सनातन विरोधियों के साथ है या खिलाफ। कार्यक्रम मे अरविंदर मुंडी, बीथिका विश्वास, राजेश गोलछा, प्रकाश शर्मा, राजेश शर्मा, विनोद पांडे, विजय साहू, हेमंत चंद्राकर, हेमंत माला, विनोद रणसिंह, महेंद्र खंडेलवाल पन्ना थवाईत, सूरज शर्मा, डीपेंद्र साहू , राजेंद्र शर्मा, अमित अग्रवाल, रोहतास मिश्रा पवन गजपाल, चिराग आथा, नीरज शुक्ला, नम्रता माला पवार , कृष्णा हिरवानी, गोविंद कोसरिया , पुष्पेंद्र बाजपेई, प्रतीक सोनी आदि उपस्थित थे।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

नए संसद भवन में होगा संसद का विशेष सत्र

नईदिल्ली। सरकार की ओर से संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर के बीच बुलाया गया है। जानकारी के मुताबिक के संसद का विशेष सत्र में संसद भवन में होगा। नए संसद भवन का उद्घाटन मई महीने में ही हुआ था। हालांकि मानसून सत्र का आयोजन पुराने संसद भवन में ही किया गया था। इसके बाद लगातार इस बात के संकेत मिल रहे थे कि शीतकालीन सत्र में संसद भवन में आयोजित हो सकते हैं। हालांकि सरकार ने 1 सितंबर को इस बात की जानकारी दी कि 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। सूत्रों ने बताया कि संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर को पुराने भवन में शुरू होगा और बाद में गणेश चतुर्थी के अवसर पर 19 सितंबर को नए भवन में स्थानांतरित किया जाएगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने 17वीं लोकसभा का यह 13वां सत्र होगा जबकि राज्यसभा का 261वां सत्र होगा।

संसद के नए सत्र का बहिष्कार नहीं करेगी कांग्रेस

नई दिल्ली। संसद के विशेष सत्र पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने पार्टी की तरफ से एक अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पार्टी संसद की विशेष सत्र का बहिष्कार करने की बजाय शामिल होने के लिए तैयार है। जयराम रमेश ने कहा, हमने संसद के विशेष सत्र का बहिष्कार नहीं करने का निर्णय लिया है। यह हमारे लिए एक मौका है, कि हम जनता की परेशानियों को सभी के सामने रखे। हर पार्टी अलग-अलग मुद्दे को सामने रखने की कोशिश करेगी। उन्होंने आगे कहा, विपक्ष के बिना चर्चा किए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे पास एजेंडे का कोई विवरण नहीं है। पार्टी ने यह फैसला मंगलवार को सोनिया गांधी की अध्यक्षता में संसदीय दल की बैठक और फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक के बाद लिया।

देश के नाम पर की जा रही राजनीति : मायावती

लखनऊ। इंडिया-भारत विवाद पर राजनीतिक उथल-पुथल के बीच, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से इस मुद्दे पर की जा रही ओछी राजनीति पर स्वत: संज्ञान लेने का आग्रह किया। लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, उन्होंने शीर्ष अदालत से देश का नाम रखने वाले सभी राजनीतिक निकायों पर प्रतिबंध लगाने का भी आग्रह किया। मायावती ने कहा कि सच तो यह है कि विपक्ष ने एक सोची-समझी साजिश के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर बीजेपी-एनडीए को संविधान में बदलाव करने का मौका दिया है। यह सत्ता पक्ष की सोची-समझी साजिश है और विपक्ष...चुनाव से पहले उन्होंने जो राजनीति की है, जनता उसे समझती है। मायावती ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को दरकिनार कर दिया है।

उदयनिधि और प्रियंक खड़गे के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

रामपुर। सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी करने के आरोप में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि और कथित रूप से उनका समर्थन करने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे के खिलाफ रामपुर में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि अधिवक्ता हर्ष गुप्ता और राम सिंह लोधी ने रामपुर की सिविल लाइंस कोतवाली में मंगलवार शाम यह मुकदमा दर्ज कराया। सूत्रों के मुताबिक, मुकदमे में उदयनिधि और प्रियंक पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और समाज में द्वेष फैलाने का आरोप लगाया गया है। मुकदमा दर्ज करवाने वाले अधिवक्ता हर्ष गुप्ता ने बताया कि चार सितंबर को अखबारों में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करते हुए उसे खत्म किए जाने की जरूरत बताए जाने संबंधी एक समाचार प्रकाशित हुआ था।

एफआईआर को लेकर भड़के प्रियंक खड़गे

नई दिल्ली। सनातन धर्म पर टिप्पणी को लेकर अधिवक्ताओं की शिकायत के आधार पर उत्तर प्रदेश के रामपुर में तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन और कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर पर प्रियंक खड़गे ने आलोचना भी की है। उन्होंने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता की वे क्या करते हैं, क्योंकि मेरा बयान किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। मैंने साफ कह कि जो धर्म समानता नहीं सिखाता है, मेरे हिसाब से वह धर्म नहीं है। उन्होंने शिकायतकर्ताओं पर कहा, उनको अगर ऐसा लगता है कि उनके धर्म में ऐसा नहीं होता है तो ये उनकी समस्या है। मेरा धर्म संविधान है और हमें जो करना होगा हम वह करेंगे। शिकायतकर्ताओं ने आरोप में कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र और कर्नाटक सरकार में ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री प्रियंक खड़गे ने सनातन धर्म पर टिप्पणी की थी। जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।

लोकसभा चुनाव पर प्रधानमंत्री बोले- 2024 में भी लोग सही चुनेंगे

जनता का हम पर अभूतपूर्व भरोसा : मोदी

नईदिल्ली। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का विश्वास जताते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लोग फिर से सही चुनेंगे। मनीकंट्रोल के साथ एक साक्षात्कार में, पीएम मोदी ने कहा कि समय और अनुभव उनके सबसे बड़े शिक्षक थे। प्रधान मंत्री ने कहा, 2014 में, कोई भी मोदी को नहीं जानता था और फिर भी उन्होंने मुझे इतने बड़े जनादेश के साथ वोट दिया। दस साल बाद, उन्होंने हर जगह थोड़ा-थोड़ा मोदी देखा है - चंद्रयान मिशन में, मेरी हाल की अमेरिका यात्रा में। अब वह वे मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोग फिर से सही चुनेंगे।

2024 के आम चुनावों में एनडीए को कड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ेगा, जिसमें 26 विपक्षी दल मोदी रथ का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त मोर्चा (आई.एन.डी.आई.ए. गठबंधन) बनाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। हाल ही में, प्यू रिसर्च सेंटर के एक अध्ययन से पता चला है कि 79 प्रतिशत भारतीयों का पीएम मोदी के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण था, जिसमें 55 प्रतिशत लोग बहुत अनुकूल दृष्टिकोण रखते थे। चुनावी राज्यों में रेवड़ी या मुफ्त उपहार देने वाले विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि वित्तीय रूप से गैर-जिम्मेदाराना नीतियों के खिलाफ सतर्क रहने की जरूरत है।

पीएम मोदी ने कहा, ऐसी नीतियों के दीर्घकालिक प्रभाव न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि समाज को भी नष्ट कर देते हैं। गरीबों को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिर भी, अच्छी बात यह है कि लोग समस्या के प्रति तेजी से जागरूक हो रहे हैं। मोदी ने कहा कि भारत के पांचवीं सबसे

बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि इसलिए हासिल हुई क्योंकि सरकार पर लोगों का भरोसा था। पीएम मोदी ने बताया कि यह हमारे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है कि लोगों ने हम पर अभूतपूर्व भरोसा किया है। उन्होंने हमें एक बार नहीं, बल्कि दो बार बहुमत का जनादेश दिया।

400 से ज्यादा सीटें जीतकर राजीव गांधी का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं मोदी

2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले तमाम मीडिया संगठन जनता के मन की बात जान रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं और अनुमान लगा रहे हैं कि फलां पार्टी को फलां सीटें मिल सकती हैं। अनुमानों में सीटों की संख्या भी बताई जा रही है और मतों का प्रतिशत भी बताया जा रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवारों के बारे में जनता क्या राय रखती है। इसके अलावा विभिन्न दल और गठबंधन भी अपनी अपनी जीत के दावे अभी से करने लगे हैं। भाजपा का कहना है कि वह पिछली बार के अपने आंकड़े 303 को पार करेगी वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया मान कर चल रहा है कि इस बार एकजुट विपक्ष स्पष्ट बहुमत हासिल करके मिलीजुली सरकार बनायेगा।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अश्विनी उपाध्याय ने दावा किया है कि भाजपा इस बार 303 नहीं बल्कि 400 के भी पार जायेगी। उन्होंने संभावना जताई है कि 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में 404 सीटें जीतकर कांग्रेस ने जो रिकॉर्ड बनाया था वह 2024 में भाजपा तोड़ सकती है। उन्होंने कहा कि मैं इस वर्ष अब तक 80 जिलों में गया हूँ और इस वर्ष के अंत तक यह आंकड़ा 100 जिलों का हो जायेगा। उन्होंने कहा कि मैं पिछले वर्ष भी 100 जिलों में गया था।

भारत के पीआईएल मैन के रूप में विख्यात अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि कॉलेजों, सामाजिक-धार्मिक संगठनों और विभिन्न क्षेत्रों में जनता खासकर युवाओं के साथ संवाद के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि 300 सीटें तो भाजपा अपने विकास के बल पर ही ले आयेगी। उन्होंने कहा कि यदि मोदी सरकार कानूनों में सुधार का सिलसिला जारी रखे और अपराध पर नियत्रंण के लिए कुछ और कड़े कानून बन जायें तो भाजपा को अकेले दम पर 400 से ज्यादा सीटें जीतने से कोई नहीं रोक सकता।

संसद के विशेष सत्र को लेकर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की तरफ से संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के बाद से ही इसे लेकर कई तरह की अटकलें लग रही हैं। एक देश-एक चुनाव से लेकर इंडिया का नाम बदलकर भारत किए जाने तक विशेष सत्र में एजेंडे को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बीच कांग्रेस की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और उनसे संसद के विशेष सत्र के एजेंडे पर जानकारी मांगी है। सोनिया गांधी ने चिट्ठी में कहा है कि संसद का विशेष सत्र विपक्ष से बिना किसी पूर्व चर्चा के बुलाया गया है। उन्होंने सत्र के एजेंडे की जानकारी भी मांगी है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने पीएम मोदी से नौ सूत्रीय एजेंडे पर चर्चा कराने का भी आग्रह किया है। उन्होंने चिट्ठी में मांग रखी कि 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र के दौरान देश की आर्थिक स्थिति, जातीय जनगणना, चीन के साथ सीमा पर गतिरोध और अदाणी समूह से जुड़े नए खुलासों की पृष्ठभूमि में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग समेत नौ मुद्दों पर उचित नियमों के तहत चर्चा कराई जाए। सोनिया गांधी ने पत्र में कहा, रचनात्मक सहयोग की भावना के तहत मैं आशा करती हूं कि संसद के आगामी सत्र में इन विषयों पर चर्चा कराई जाएगी। उनकी इस चिट्ठी पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि किसी को भी इस विशेष सत्र को लेकर जानकारी नहीं थी। पहली बार ऐसा हो रहा है, जब विशेष सत्र को लेकर हमारे पास एजेंडे की कोई जानकारी ही नहीं है।

इंडिया गठबंधन की हुई बड़ी बैठक

यह लोकतंत्र चलाने का तरीका नहीं : खड़गे

नईदिल्ली। इंडिया गठबंधन के विपक्षी दलों ने मंगलवार को मांग की कि सरकार 18 से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र के एजेंडे में पारदर्शिता बनाए रखे और देश को अंधेरे में न रखे। साथ ही उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक को जल्द पारित करने का भी आह्वान किया। सूत्रों ने कहा कि पूर्व कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी आगामी सत्र के दौरान लोकसभा में विधेयक को शीघ्र पारित कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगी क्योंकि यह विधेयक राज्यसभा में पहले ही पारित हो चुका है। एक बैठक में विपक्षी दलों ने आगामी सत्र में एक साथ चलने और अडानी मुद्दे को भी उठाने का फैसला किया। उन्होंने भारत पार्टियों की पहली संयुक्त सार्वजनिक रैली मध्य प्रदेश में और अगली बैठक भोपाल में आयोजित करने का भी निर्णय लिया।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि बैठक में सभी की राय थी कि ये विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है? सरकार की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण आज तक नहीं आया है। लगभग 12-13 दिन बाद संसद का एक विशेष सत्र होने वाला है और देश को नहीं पता कि इस विशेष सत्र की विशेषता क्या है? तो हमारी मांग ये है कि बीजेपी पारदर्शिता दिखाए और देश को अवगत कराए कि इस विशेष सत्र का विशेष एजेंडा क्या है? दिल्ली में इंडिया अलायंस के फ्लोर लीडर्स की बैठक के बाद डीएमके सांसद टीआर बालू और तिरुचि शिवा ने कहा कि हमने इस मामले पर चर्चा की है। वे प्रत्येक मामले को एक साथ उठा रहे हैं। पत्र अंतत: प्रधान मंत्री को भेजा जाएगा।

खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार पहली बार बिना एजेंडा बताए संसद का विशेष सत्र बुला रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी विपक्षी दल से न तो सलाह ली गई और न ही जानकारी दी गई। यह लोकतंत्र चलाने का तरीका नहीं है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, क्या आपने कभी ऐसी सरकार देखी है जिसका विपक्ष के साथ संवाद न हो? यह विशेष सत्र। उन्होंने यह सत्र क्यों बुलाया है?...

एमडीएमके नेता वाइको ने कहा, प्रधानमंत्री इस देश को राष्ट्रपति शासन वाली सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही उनका अंतिम उद्देश्य है। हमें लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ना होगा। इसलिए, हम इस बारे में चर्चा करेंगे।

इंडिया गठबंधन को पंजाब में बड़ा झटका एकला चलो की राह पर आप और कांग्रेस

इंडिया ब्लॉक को झटका देते हुए, आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई ने पंजाब में कांग्रेस के साथ सीटें साझा करने से इनकार कर दिया है। पंजाब की मंत्री अनमोल गगन मान ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर चीजें अलग हो सकती हैं क्योंकि देश को बीजेपी से बचाने के लिए सभी पार्टियां एक साथ आई हैं लेकिन राज्य में आप कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी नेतृत्व का आह्वान है। लेकिन हम पंजाब में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर चीजें अलग हो सकती हैं क्योंकि देश को बीजेपी से बचाने के लिए सभी पार्टियां (भारत गठबंधन) एक साथ आ गई हैं। हालांकि राज्य स्तर पर आप कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी। हम पंजाब में कांग्रेस के साथ सीटों का बंटवारा बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी ओर पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा कि फिलहाल, हमें सभी 13 लोकसभा सीटों पर तैयारी करने और सभी 13 सीटों के लिए अपेक्षित उम्मीदवारों के नाम बताने के लिए कहा गया है। हाईकमान सर्वोच्च है। आलाकमान हम पर चीजें थोपता नहीं है, वे हमेशा हमारी बात सुनते हैं और हमें विश्वास में लेते हैं। अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने मंगलवार को घोषणा की थी कि राज्य में आम आदमी पार्टी (आप) के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा।

खेल
प्रमुख समाचार

वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान

सिडनी। पैट कमिंस, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क और ग्लेन मैक्सवेल को चोटों के बावजूद भारत में होने वाले विश्व कप के लिये आस्ट्रेलिया की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है जबकि गेंदबाजी हरफनमौला सीन एबोट पहली बार टूर्नामेंट में खेलेंगे। कमिंस और स्मिथ कलाई की चोट से जूझ रहे हैं जो उन्हें एशेज श्रृंखला के दौरान लगी थी । वहीं स्टार्क और मैक्सवेल ग्रोइन और टखने की चोट का शिकार हैं।

आस्ट्रेलिया के मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने कहा ," ये सभी जल्दी ही फिट हो जायेंगे और भारत के खिलाफ आगामी श्रृंखला में उनके चयन की उम्मीद है । विश्व कप की अंतिम टीम के ऐलान से पहले भारत और दक्षिण अफ्रीका में आठ वनडे मैच खेलने हैं।" एडम जाम्पा और एश्टोन एगर दो स्पिनरों को टीम में जगह मिली है जबकि जोश इंगलिस बैकअप विकेटकीपर हैं। टीम में 28 सितंबर तक बदलाव किया जा सकता है।

आस्ट्रेलिया को दक्षिण अफ्रीका में पांच वनडे मैचों की श्रृंखला और भारत में तीन वनडे खेलने हैं। विश्व कप से पहले उसे नीदरलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ अभ्यास मैच खेलने हैं। विश्व कप में उसे आठ अक्टूबर को चेन्नई में भारत के खिलाफ पहला मैच खेलना है।

आस्ट्रेलिया टीम

पैट कमिंस (कप्तान), सीन एबोट, एश्टोन एगर, एलेक्स कारी, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस, मिचेल स्टार्क, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ, मार्कस स्टोइनिस, डेविड वॉर्नर, एडम जाम्पा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 100 अंक चढ़ा निफ्टी 19,600 के पार

नईदिल्ली। लोबल मार्केट से मिले नकारात्मक रुझानों के बीच हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को घरेलू शेयर बाजार लगातार चौथे दिन हरे निशान पर बंद हुए। दोनों फ्रंटलाइन इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में हल्की बढ़त दर्ज की गई। आज के कारोबार में बीएसई सेंसेक्स ने 100 अंकों की बढ़त दर्ज की। वहीं, निफ्टी में भी 36 अंको की बढ़त दर्ज की गई। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 100.26 अंक यानी 0.15 फीसदी की बढ़त के साथ 65,880.52 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 65,971.13 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 65,488.03 तक आया। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 36.15 अंक यानी 0.18 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी दिन के अंत में 19,611.05 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी 19,636.45 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 19,491.50 तक आया।

वेदांता को मिली जांबिया की कॉपर माइन की ओनरशिप

नईदिल्ली। भारतीय अरबपति अनिल अग्रवाल की वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने जांबिया की एक कॉपर माइन कंपनी का मालिकाना हक वापस ले लिया है। कंपनी ने चार साल की कानूनी लड़ाई के बाद इस विवाद को सुलझा लिया है। इस बात की घोषणा कंपनी ने 5 सितंबर को की। वेदांता रिसोर्सेज ने बयान में कहा कि जांबिया की सरकार ने कोंकोला कॉपर माइन्स की ओनरशिप और ऑपरेशनल कंट्रोल को वेदांता सिसोर्सेज को वापस कर दिया है। जांबिया के मिनिस्टर ऑफ माइन्स एंड मिनरल्स डेवलपमेंट पॉल काबुस्वे ने कहा कि केसीएम की ओनरशिप को मेजारिटी शेयरहोल्डर के रूप में वेदांता को फिर से सौंपा जा रहा है। अनिल अग्रवाल की कंपनी के पास केसीएम की 79.4 फीसदी हिस्सेदारी है।

चीनी का कीमत 15 दिनों में 3 फीसदी बढ़ी

नईदिल्ली। देश में चीना की कीमतों के भाव आसमान छू रहे हैं। चीनी के घरेलू दाम इस समय 6 सालों के हाई लेवल पर हैं। बाजार की मानें तो चीनी के कम उत्पादन की आशंका के चलते भाव में इतना इजाफा हुआ है। वहीं चीनी के दामों के बढ़ने के पीछे एक फैक्टर मॉनसून भी है। इस साल मानसून में कमजोरी के चलते भी भावों में उछाल देखा गया है। इलका कारण ये है कि कमजोर मॉनसून रहा तो देश में गन्ने के उत्पादन पर बुरा असर पड़ सकता है। इसी आशंका के चलते चीनी की कीमतें सितंबर 2017 के बाद सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच चुकी है। बीते 15 दिनों में चीनी के दाम में 3 फीसदी तक का इजाफा दर्ज किया गया है। देश में त्योहारी सीजन में चीनी की मांग बढ़ने की संभावना है जिसके कारण भी चीनी के दाम चढ़े है। देश के जो प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य हैं वहां पर कम बारिश हुई है। इसी के चलते देशभर में गन्ना उत्पादन की कमी को लेकर आशंका पैदा हो गई है।

ज्यूपिटर लाइफ लाइन का आईपीओ खुल गया

नईदिल्ली। मल्टी-स्पेशियलिटी हेल्थकेयर सेवा कंपनी ज्यूपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल्स लिमिटेड की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश आज, 6 सितंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया। जुपिटर लाइफ लाइन आईपीओ का प्राइज बैंड 695 से 735 प्रति शेयर तय किया गया है और ऑफर शुक्रवार, 8 सितंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। ज्यूपिटर लाइफ लाइन के आईपीओ इश्यू का आकार 869.08 करोड़ रुपये का है। इसमें से 542 करोड़ रुपये के नए इक्विटी शेयर जारी किये जाएंगे। साथ ही कंपनी के आईपीओ में प्रमोटर समूह कंपनियों समेत अन्य शेयरधारकों द्वारा 44.5 लाख इक्विटी शेयरों की बिक्री की पेशकश शामिल है। ज्यूपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल्स आईपीओ के लिए लॉट साइज 20 शेयर है और रिटेल निवेशकों के लिए आवश्यक न्यूनतम निवेश राशि 14,700 रुपये है।

वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की विकास दर का बढ़ना उत्साहजनक

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

इसमें कोई दो राय नहीं कि विपरीत हालातों के बावजूद देश की आर्थिक विकास दर के आंकड़े लगातार उत्साह जनक सामने आ रहे हैं। खास बात यह है कि चालू वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही के आंकड़े आशा से अधिक बेहतर रहने के साथ ही पिछले वित्तीय वर्ष की चारों तिमाही से अधिक रहे हैं। यह सब तो तब है जब दुनिया के देश अभी आर्थिक संकट के दौर से ही गुजर रहे हैं। पड़ोसी पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं तो अन्य देशों की अर्थ व्यवस्था भी हालातों से जूझ रही है। दरअसल कृषि क्षेत्र बड़ा सहारा बन कर उभर कर आता रहा है। हालांकि आने वाली तिमाही कृषि क्षेत्र के लिए अनुकूल इसलिए नहीं मानी जा सकती कि देश में मानसून धोखा देता दिखाई दे रहा है। देष के अधिकांश हिस्सों में मानसून के आंकड़े निराशाजनक आ रहे हैं। यह सर्वविदित है कि खरीफ की फसल लगभग पूरी तरह मानसून पर निर्भर करती है और मानसून ने जिस तरह से अगस्त माह में बेरुखी दिखाई है उससे कृषि जगत में निराशा आई है। मौसम विज्ञानियों की मानें तो सितंबर माह में भी मानसून के जो संकेत मिल रहे हैं वह निराशाजनक ही आ रहे हैं। किसानों की ललाट पर चिंता की रेखा साफ दिखाई दे रही है। अब तो मानसून की बेरुखी से सरकार भी चिंता में आ गई है।

दरअसल कृषि क्षेत्र इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश में सर्वाधिक रोजगार के अवसर कृषि क्षेत्र से ही आते हैं तो कृषि क्षेत्र ने भारतीय अर्थ व्यवस्था को बड़ा सहारा दिया है। कोरोना काल में कृषि क्षेत्र ने अर्थ व्यवस्था ही नहीं बल्कि देश के लोगों खासतौर से गरीब लोगों को जो राहत दी है वह अतुलनीय रही है। आज भी देश के

गोदाम अन्न धन से भरे हैं तो देश कम से कम अन्नधन को लेकर तो बेफ्रिक है। हालांकि कृषि क्षेत्र के लिए चुनौती भरा समय आ गया है पर देश के अन्नदाता की मेहनत पर सबको भरोसा है। दरअसल चालू वित वर्ष की पहली तिमाही के जो आंकड़े एनएसओ ने जारी किए हैं वह उत्साहवर्द्धक हैं। जारी आंकड़ों के अनुसार जून 23 तिमाही में कृषि क्षेत्र में मूल्य सवंर्द्धन 3.5 फीसदी रहा है जो एक साल पहले की इसी अवधि के 2.4 प्रतिशत से कहीं अधिक है। यह परिणाम समग्र प्रयासों से ही संभव हो सके हैं। समग्र रूप से देखा जाए तो अप्रैल-जून तिमाही जीडीपी में वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत रही है हालांकि आरंभिक अनुमान 8 प्रतिशत से नीचे रहने के बावजूद अर्थ व्यवस्था के सकारात्मक दिशा में बढ़ने के तो स्पष्ट संकेत हैं ही।

देखा जाए तो इस दौरान रियल एस्टेट, फाइनेंस और सर्विस सेक्टर में भी अच्छी विकास दर रही है। अब देश में त्यौहारी सीजन आरंभ हो जाने से यह माना जा रहा है कि दिसंबर तक देश की अर्थ व्यवस्था कुलाचे भरने की स्थिति में रहेगी। बाजार में मांग बढ़ेगी तो इससे उत्पादन और वितरण दोनों ही क्षेत्रों में अर्थ व्यवस्था में उछाल आयेगा। कोराबारियों की मानें तो त्यौहारी सीजन में बाजार और अधिक गुलजार रहेगा और अर्थ व्यवस्था को पंख लगेंगे। हालांकि मानसून की बेरुखी का असर भी देखने को मिल सकता है। ऐसे हालातों में कृषि से इतर अन्य सेक्टरों को बेहतर परिणाम देने होंगे ताकि आर्थिक विकास की दर बनी रहे। थोड़ा चिंतनीय इसलिए अवश्य है कि पहली तिमाही में निर्यात और विनिर्माण क्षेत्र में सुस्ती दिखाई दी है। ऐसे में चुनौतियां और अधिक हो जाती हैं। भले ही हमारी आर्थिक विकास दर संभली हुई ही नहीं अपितु बढ़ रही है। पर चिंता के कारण यथावत हैं। जो हालात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिल रहे हैं उससे अधिक आशा की जानी बेमानी ही होगी। अपितु अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र में जो सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं उसे सकारात्मक ही माना जाएगा क्योंकि दुनिया के हालात जस के तस हैं। दूसरी ओर विदेशों के हालात देखें तो रूस यूक्रेन युद्ध समाप्ति के दूर-दूर तक कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। चीन की बौखलाहट सामने है तो अमेरिका और योरोपीय देशों के आर्थिक व राजनीतिक हालात कोई आशाजनक नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में दुनिया के देशों के आर्थिक हालात को लेकर कोई आशा नहीं की जा सकती।

गिलगित की आवाज दबा रहे पाक के हुक्मरान

राजेश बादल

यह दिलचस्प है कि साम्प्रदायिक आधार पर बने पाकिस्तान में ही साम्प्रदायिकता के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान में दिनोंदिन बढ़ रहे तनाव के मद्देनजर चेतावनी जारी की है कि वहां साम्प्रदायिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो लोग साम्प्रदायिकता फैलाने का प्रयास करेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। चिलास कस्बे की दिया मीर युवा उलेमा कौंसिल के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल मलिक तो साफ-साफ कहते हैं कि जब तक साम्प्रदायिकता भड़काने वालों को सरकारी संरक्षण दिया जाता रहेगा, तब तक इस खूबसूरत प्रदेश में शांति बहाल होना मुश्किल है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पश्चिमी और यूरोपीय देश अपने नागरिकों को पाकिस्तान के इस इलाके में नहीं जाने की सलाह दे रहे हैं। अमेरिका ने अपने देश के लोगों से कहा है कि पाकिस्तान के इस उत्तरी भाग में जाना खतरे से खाली नहीं है। कमोबेश ऐसी ही चेतावनी ब्रिटेन ने भी अपने निवासियों को दी है। उसने कहा है कि इस इलाके में साम्प्रदायिक तनाव चरम पर है और गोरों को वहां की यात्रा टालनी चाहिए। कनाडा ने भी ऐसी एडवाइजरी जारी की है। दरअसल गिलगित इलाके में शिया आबादी बहुतायत में रहती है। ईरान में सबसे अधिक शिया रहते हैं। उसके बाद भारत में शियाओं की संख्या है। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में लगभग दस लाख शिया मुसलमान रहते हैं। वहां जब तब शिया-सुन्नी टकराव होता रहता है। सुन्नी उन्हें सम्प्रदाय से बाहर बताते हैं और जब भी दोनों मुस्लिम समुदायों में संघर्ष होता है, पाकिस्तान सरकार उसे साम्प्रदायिक तनाव बताती है। इसी तरह सुन्नी मुस्लिम अहमदिया मुसलमानों, बोहराओं, बलूचियों को अपने मजहब से बाहर का मानते हैं। भारतीय मुस्लिमों को वे मुहाजिर कहते हैं और उन्हें दोयम दर्जे का बताते हैं। कोई पाकिस्तान के सुन्नियों और फौज को बताए कि उनके कायदे आजम जनाब मुहम्मद अली जिन्ना ने तो भारत में ही रहते हुए पाकिस्तान जाने की अपील सारी मुस्लिम जातियों - उप जातियों से की थी। वे स्वयं भी मुंबई से पाकिस्तान गए थे। इस तरह तो वे भी मुहाजिर ही थे। जिन्ना ने तो कभी मुसलमानों के बीच किसी तरह का फर्क नहीं किया, मगर उनकी उत्तराधिकारी फौज ने सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए सुन्नियों का सहारा लिया और आज एक मुस्लिम मुल्क में मुसलमान ही मुसलमान नहीं समझे जाते। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। बहरहाल, लौटते हैं गिलगित - बाल्टिस्तान के ताजे घटनाक्रम पर। पाकिस्तान सरकार दशकों से वहां धीरे-धीरे खामोशी से सुन्नियों को बसाने का काम करती रही है। इसका विरोध भी समय-समय पर होता रहा है। मौजूदा हाल यह है कि सुन्नियों की आबादी शियाओं से करीब दो गुनी हो चुकी है। इसलिए वहां के मूल निवासी पाकिस्तान सरकार के इस रवैये के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करते रहते हैं। यह प्रांत ताजिकिस्तान, चीन और भारत के कारगिल -द्रास की ओर से जुड़ता है। सीमांत संवेदनशील प्रदेश होने के कारण यहां की हर घटना पाकिस्तान की केंद्रीय सत्ता को चिंता में डाल देती है। चीन अपना ग्वादर तक जाने वाला गलियारा भी इसी क्षेत्र से बना रहा है। गिलगित के स्थानीय निवासी इसके हमेशा विरोध में रहे हैं। वे यदा-कदा भारत में वापस विलय की मांग भी करते रहते हैं और कारगिल का रास्ता खोलने के लिए भी आवाज उठाते रहते हैं। यह बात आईएसआई और पाकिस्तानी सेना को रास नहीं आती। वे जब स्थिति पर नियंत्रण नहीं कर पाते, तो आरोप लगाते हैं कि गिलगित - बाल्टिस्तान में अशांति के पीछे हिंदुस्तान का हाथ है।

चुनाव के लिए कितना तैयार है गठबन्धन ?

आनंद पांडे

कुछ समय पहले तक यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि 2024 में 27 विपक्षी दल एक साथ आकर एक मजबूत विकल्प के रूप में केंद्रीय सत्ता के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। पर अब यह एक हकीकत है कि अपने तमाम मतभेदों, वैचारिक भिन्नताओं के बावजूद ये दल अब काफी हद तक इंडिया नामक गठबन्धन में बंध गए हैं।

पटना, बेंगलुरु और मुंबई की तीन शिखर बैठकों के बाद ये दल गठबन्धन की दिशा में इतनी दूर तक आगे बढ़ चुके हैं कि इनमें से अब किसी एक का भी पीछे लौटना उसकी राजनीतिक साख के लिए घातक साबित हो सकता है। इसलिए अब यह मानकर चलना होगा कि इंडिया गठबन्धन अब एक नई राजनीतिक सच्चाई है, जो आगामी आम चुनावों में जनता को आश्वस्त और अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी क्षमता रखता है। यह एक ऐसी सच्चाई बन चुका है, जिसे सत्तापक्ष व जनता द्वारा हल्के में नहीं लिया जाएगा। इस गठबन्धन पर अनाप-शनाप टीका-टिप्पणी करके, अंतर्विरोधों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाकर और मजाकिया नाम देकर इसे सत्ता की दौड़ से दूर दिखाना, असंभव हो गया है। इसके अलावा यह भी स्वीकार करना होगा कि चुनाव पूर्व और चुनाव बाद इंडिया गठबन्धन के घटक दलों की संख्या बढ़नी ही है, घटनी नहीं है।

राजनीति के सामाजिक आधारों की बात करें तो इसका आधार पिछड़े, आदिवासी, दलित व अल्पसंख्यक समुदायों में है, जो आबादी की दृष्टि से बहुसंख्यक हैं। संभवत: इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी ने मुंबई में दावा किया कि गठबन्धन देश की 60 फीसदी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, इसे हराना असम्भव है। यदि सामाजिक बहुमत राजनीतिक बहुमत में बदल सके तो यह गठबन्धन सत्ता में भी आ सकता है।

यह गठबन्धन एक ऐसा देशव्यापी गठबन्धन है जो 11 बड़े राज्यों में सरकार में है, विधायकों की संख्या की दृष्टि से एनडीए से थोड़ा ही कम है, लोकसभा में इसके 142 और राज्यसभा में 98 सांसद हैं। इसके पास एनडीए के विपरीत प्रधानमंत्री पद के लिए कोई तय चेहरा भले न हो

लेकिन देश के कई वरिष्ठ, अनुभवी और जनाधार वाले नेता हैं जिनके पास चुनावी राजनीति और प्रशासन का अप्रश्नेय अनुभव है।

मुंबई बैठक के बाद संयोजक, मीडिया व संचार और चुनाव रणनीति व प्रचार समितियों के गठन से यह पता चलता है कि ये दल अब मिलकर कार्रवाई करने को तैयार हैं। सहयोग अब केवल शीर्ष नेताओं की बैठकों तक ही सीमित नहीं रह गया है। इस बैठक के बाद संयुक्त बयान में आगामी दिनों में देश के अनेक भागों में बड़ी जनसभाओं के आयोजन की भी बात कही गयी है। इसके अलावा इसी माह के अंत तक सीटों के बँटवारे को लेकर भी फैसले लिए जाने की बात सामने आई है। कहने का आशय यह है कि स्वयं को 2024 में मतदाताओं के सामने सत्ता के दावेदार विकल्प के रूप में पेश करने के लिए इंडिया गठबन्धन एक-एक करके धीरे-धीरे अपनी सभी बाधाएँ दूर करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है।

फिर भी इसकी कामयाबी और एकजुटता के मामले में मुख्यधारा के मीडिया संस्थानों और एनडीए नेताओं को छोड़ भी दें तो भी अब भी कुछ राजनीतिक प्रेक्षक और टीकाकार यह अंदेशा जताते हैं कि गठबन्धन अंतत: आंतरिक विघटन का शिकार होकर सुस्त हो जाएगा और परिणामस्वरूप मतदाताओं की नजरों में नहीं चढ़ पायेगा। राजनीति संभावनाओं का खेल है। इसमें कभी भी कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता है जैसा कि महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ हो चुका है। ऐसा और भी किसी प्रदेश में किसी दल के साथ हो सकता है। पर 2024 में नई सरकार का गठन दलबदल और पार्टियों को तोड़कर नहीं, बल्कि मतदाताओं के दिल जीतने की अग्निपरीक्षा से गुजरने के बाद होना है। ऐसे में संभावनाओं के द्वार पूरी तरह से खुले हुए हैं।

ऐसे प्रेक्षक और टीकाकार उन सकारात्मक तत्त्वों और राजनीतिक वास्तविकताओं की उपेक्षा करते हैं जिन्होंने ऐसे विशाल और बहुरंगी गठबन्धन की असम्भव संभावना को संभव बना दिया है। कांग्रेस को छोड़कर सभी पार्टियों के शीर्ष नेता या तो राज्यों में सरकार चला रहे हैं या फिर उनका पूरा ध्यान राज्य में सत्ता हासिल करने पर है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार पहले तो उम्र के कारण और दूसरे अपनी पार्टी को एकजुट न रख पाने के कारण प्रधानमंत्री की रेस से बाहर हैं। सीपीएम में प्रधानमंत्री बनने लायक कोई दूसरा ज्योति बसु नहीं है, और उसे कोई मुग़ालता भी नहीं है। डीएमके के नेता स्टालिन राज्य में ही खुश हैं। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं ही, और 2024 के बाद भी बने रह सकने की संभावना से भरे हुए हैं। ऐसे में वे प्रधानमंत्री न भी बने तो उनका कोई नुकसान नहीं है, सिवाय नीतीश कुमार के, जिन पर तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री की गद्दी खाली करने का दबाव हो सकता है। क्षेत्रीय दलों का कोई और नेता दिल में भले पीएम बनने की लालसा पाले हो पर सामने शायद ही आये।

राहुल गांधी ने भले ही अपनी इच्छा न जाहिर की हो पर कांग्रेस के नेता व मुख्यमंत्री निजी हैसियत में उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बता चुके हैं। इसके बावजूद राहुल गांधी भी सत्ता के लिए बेचैन नहीं हैं बल्कि वे भाजपा को बेदखल करने में ज्यादा रुचि रखते हैं। वे तभी प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे जब उनकी पार्टी की सीटें स्थिति मजबूत हो। इसके लिए उसे 150 से अधिक सीटें जितनी होंगी। अभी तक के माहौल में यह मुश्किल लगता है पर चुनाव नजदीक आने पर जनता उसके पक्ष में मूड बना ले तो यह हो भी सकता है। उसका आधार अब भी बहुत बड़ा है। ऐसे में इंडिया घटक दलों का कोई नेता पीएम बनने के लिए बेचैन हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। यह एक सकारात्मक बात है जो गठबन्धन को बांधे रह सकती है।

लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम अपनी पार्टियों के नुकसान करके भी साथ चुनाव लड़ेंगे। ऐसा और पार्टियां भी सोचती होंगी। इसका कारण यह है कि इन पार्टियों के शीर्ष नेताओं को निजी स्तर पर कोई नुकसान नहीं उठाना है और न ही त्याग का कष्ट करना है। वे तो पार्टी के दूसरे नेता होंगे जो सीटें सहयोगी दलों के खाते में चले जाने के बाद नुकसान का खामियाजा भुगतेंगे। पर वे भी शायद न पार्टी का कुछ नुकसान करने की स्थिति में होंगे न शीर्ष नेतृत्व को नाराज करने की स्थिति में। ऐसे में सीटों का बंटवारा भी आसानी से हो सकता है।

पर इंडिया गठबन्धन इस महत्वाकांक्षा में नहीं जी रहा है कि उसे एक सीट पर एक ही उम्मीदवार देना है। मुंबई बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया है %जहाँ तक संभव होगा हम मिलकर लड़ेंगे। यानि कि जहाँ बीजेपी या एनडीए या गुटनिरपेक्ष दलों से उनकी टक्कर नहीं है, जहाँ घटक दल आपस में ही एक दूसरे के मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं वहाँ वे अलग-अलग चुनाव लड़ने के विकल्प खुले रखे हुए हैं। बंगाल व केरल इसके लिए सबसे प्रासंगिक राज्य हैं। दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस और आप मिलकर भी लड़ सकते हैं। रणनीति की यह उदारता भी गठबन्धन की एक शक्ति है। चुनाव लड़ने की इस उदार रणनीति ने उसकी राह आसान कर दी है।

इनके अलावा एक और सकारात्मक बात है जो विपक्षी गठबन्धन को आंतरिक विघटन से बचाये हुए है। वह है गठबन्धन के संयोजक व प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर किसी एक नेता के नाम पर चुनाव पूर्व आमराय न बनाने की कोशिश। नेता के बजाय टीम की तरह काम करना भी उसका एक अच्छी रणनीति है। कुल मिलाकर कहें कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के सिवा अन्य घटक दलों को खोने के लिए कुछ खास नहीं है जबकि पाने के लिए सारा जहाँ है!

भारतीय ज्ञान परंपरा....

नृसिंहपूर्वतापिन्युपनिषद् (भाग-16)

यह एक लघुकाय उपनिषद् है। यह उपनिषद् देवताओं और प्रजापति के मध्य हुए प्रश्नोत्तर से प्रकट हुई है। एक बार देवों ने प्रजापति से नारसिंह चक्र के सम्बन्ध में जिज्ञासा की, जिसका समाधान प्रजापति ने प्रदान किया। प्रजापति ने नारसिंह चक्र की संख्या छह बताई। इसी आधार पर इस उपनिषद् की नृसिंहषट्चक्रोपनिषद् संज्ञा हुई। छहों चक्रों का नाम बताते हुए प्रजापति ने कहा- प्रथम आचक्र, द्वितीय सुचक्र, तृतीय महाचक्र, चतुर्थ सकललोक रक्षणचक्र, पंचम द्यूत चक्र और षष्ठ असुरान्तक चक्र है। तत्पश्चात् देवों ने तीन वलय और उनके भेदों प्रभेदों की बात पूछी है, जिसे प्रजापति ने बड़ी स्पष्टता से उत्तर दिया है। पुन: देवों ने इन चक्रों को धारण करने के स्थान के विषय में प्रश्न पूछा, तब प्रजापति ने इनके धारण करने के स्थान तथा धारण करने के लाभ भी बताए हैं। अन्त में इस उपनिषद् के अध्ययन की फलश्रुति बताते हुए उपनिषद् को पूर्णता प्रदान की गई है। ? देवा ह वै सत्यं लोकमायंस्तं प्रजापतिमपृच्छन्नारसिंहचक्रन्नो ब्रूहीति । तान्प्रजापति- एक बार देवताओं ने सत्यलोक में पहुँचकर प्रजापति (ब्रह्माजी) से कहा- आप हमें नारसिंह चक्र का उपदेश प्रदान करने की कृपा करें। तदुपरान्त प्रजापति ने उन समस्त देवों को नारसिंह चक्र का उपदेश प्रदान किया, जो इस प्रकार है- नारसिंह चक्र की संख्या छ: होती है। प्रथम चक्र चार अर वाला, द्वितीय भी चार अर वाला, तृतीय आठ अर वाला, चतुर्थ पाँच अर वाला, पंचम भी पाँच अर वाला तथा छठवाँ आठ अर वाला है। इस तरह से ये छ: नारसिंह चक्र कहलाते हैं ॥ 1॥

देवों के द्वारा यह पूछने पर कि उनके क्या-क्या नाम हैं? यह सुनकर प्रजापति ने कहा कि प्रथम आचक्र, दूसरा सुचक्र, तीसरा महाचक्र, चौथा सकललोक रक्षणचक्र, पाँचवाँ द्यूतचक्र एवं छठवाँ असुरान्तक चक्र के नाम से प्रख्यात है। ये ही छ: नारसिंह चक्रों के नाम हैं ॥ 2॥

तदनन्तर देवों द्वारा यह पूछे जाने पर कि उसके तीन वलय कौन-कौन से होते हैं? प्रजापति ने बताया कि प्रथम आन्तर, द्वितीय मध्यम और तृतीय बाह्य है। ये ही तीन वलय कहलाते हैं। इनमें से जो मध्यम बीज है, वह नारसिंह गायत्री और जो बाह्य है, वही मन्त्र है ॥ 3॥

आन्तर वलय कितने हैं? देवों द्वारा यह पूछे जाने पर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा कि आन्तर वलयों की संख्या छ है । नारसिंहम् पहले का है, महालक्ष्म्यं दूसरे का सारस्वत तीसरे का है, जिन लोगों का जो इष्टदेव हो, वह चौथे का है, ओंकार पाँचवें का और क्रोध दैवत छठे का नाम है। अत: ये छ: नारसिंह चक्रों के छ: आन्तर वलय हैं ॥ 4॥

भवन्ति ॥ 5॥ देवों ने जब यह पूछा कि मध्यम वलयों की संख्या कितनी है ? तो प्रजापति जी ने उत्तर दिया कि मध्यम वलयों की संख्या भी छ: ही है। नारसिंहाय प्रथम का है, विद्महे दूसरे का, वज्रनखाय तीसरे का है, धीमहि चौथे का, तन्त्र पाँचवें का, सिंह: प्रचोदयात् छठे का नाम है अत: ये छ: नारसिंह चक्रों के छ: मध्यम वलय होते हैं ॥ 5॥

क्रमश:

दूसरा गोलमेज सम्मेलन

दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित हुआ। उसमें गाँधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। गाँधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इस दावे को तीन पार्टियों ने चुनौती दी। मुस्लिम लीग का कहना था कि वह मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में काम करती है। राजे-रजवाड़ों का दावा था कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है। तीसरी चुनौती तेज-तर्रार वकील और विचारक बी आर अंबेडकर की तरफ़ से थी जिनका कहना था कि गाँधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। लंदन में हुआ यह सम्मेलन किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सका इसलिए गाँधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा। भारत लौटने पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया।

नए वायसराय लॉर्ड विलिंग्डन को गाँधी जी से बिलकुल हमदर्दी नहीं थी। अपनी बहन को लिखे एक निजी खत में विलिंग्डन ने लिखा था कि- अगर गाँधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। वह जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहता है लेकिन असल में उसके पीछे एक गहरी राजनीतिक चाल होती है। देखता हूँ कि अमेरिकी प्रेस उसको गज़ब का आदमी बताती है। लेकिन सच यह है कि हम निहायत अव्यावहारिक, रहस्यवादी और अंधिविश्वासी जनता के बीच रह रहे हैं जो गाँधी को भगवान मान बैठी है।

बहरहाल, 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट में सीमित प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया। दो साल बाद सीमित मताधिकार के आधिकार पर हुए चुनावों में कांग्रेस को जबर्दस्त सफ़लता मिली। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रतिनिधि सत्ता में आए जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम करते थे। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के सत्ता में आने के दो साल बाद, सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। महात्मा गाँधी और जवाहरलाल नेहरू, दोनों ही हिटलर व नात्सियों के कड़े आलोचक थे। तदनुरूप, उन्होंने फ़ैसला लिया कि अगर अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राजी हों तो कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में सहायता दे सकती है। सरकार ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफ़ा दे दिया। सम्मेलन के दौरान, गांधीजी मुस्लिम प्रतिनिधित्व और सुरक्षा उपायों पर मुसलमानों के साथ कोई समझौता नहीं कर पाए। सम्मेलन के अंत में रामसे मैकडोनाल्ड ने अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के संबंध में एक सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की और उसमें यह प्रावधान रखा गया कि राजनीतिक दलों के बीच किसी भी प्रकार के मुक्त समझौते को इस निर्णय के स्थान पर लागू किया जा सकता है। गांधी ने अछूतों को हिन्दू समुदाय से अलग एक अल्पसंख्यक समुदाय का दर्ज़ा देने के मुद्दे का गांधी ने खुलकर विरोध किया। उनका बी.आर. अम्बेडकर के साथ अछूतो को दिये गये दो मताधिकार तथा अलग राष्ट्र की मांग वाले मुद्दों पर लगभग 15 दिन विवाद हुआ। उस समय गांधी ने आमरण अनशन(हड़ताल) की थी अंतत: दोनों नेताओं ने इस समस्या का हल 1932 की पूना संधि द्वारा निकाला। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के नाम से एक पृथक राष्ट्र की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया और उसे अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। अब राजनीतिक भूदृश्य काफ़ी जटिल हो गया था- अब यह संघर्ष भारतीय बनाम ब्रिटिश नहीं रह गया था। अब यह कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश शासन, तीन धुरियों के बीच का संघर्ष था। इसी समय ब्रिटेन में एक सर्वदलीय सरकार सत्ता में थी जिसमें शामिल लेबर पार्टी के सदस्य भारतीय आकांक्षाओं के प्रति हमदर्दी का रवैया रखते थे लेकिन सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कट्टर साम्राज्यवादी थे। उनका कहना था कि उन्हें सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नहीं नियुक्त किया गया है कि वह ब्रिटिश साम्राज्य को टुकड़े-टुकड़े कर दें।

मोहब्बत बनाम नफरत का अक्स

बलबीर पुंज

कथित मोहब्बत की दुकान से बेचे जाने वाली वस्तुओं के नमूने उपलब्ध होना आरंभ हो गए हैं। चेन्नई में 2 सितंबर को एक कार्यक्रम में उदयनिधि स्टालिन ने कहा, कुछ चीजें हैं, जिनका हमें उन्मूलन करना है और हम केवल उनका विरोध नहीं कर सकते। मच्छर, डेंगू, मलेरिया, कोरोना, ये सभी चीजें हैं, जिनका हम विरोध नहीं कर सकते, हमें इन्हें मिटाना है। सनातन धर्म भी ऐसा ही है, इसे खत्म करना... हमारा पहला काम होना चाहिए। बकौल उदयनिधि, ...सनातन समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। उदयनिधि कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। वह तमिलनाडु की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) गठबंधन सरकार में मंत्री, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पुत्र और उस आईएनडीआईए गठबंधन (कांग्रेस सहित) का हिस्सा हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी भी कीमत पर सत्ता से हटाना चाहता है।

जैसे ही उदयनिधि ने उपरोक्त विचार प्रस्तुत किए, तमिलनाडु सरकार में सहयोगी कांग्रेस के दो नेताओं- सांसद कार्ति चिदंबरम और पार्टी की प्रदेश ईकाई की महासचिव लक्ष्मी रामचंद्रन ने इसका समर्थन कर दिया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए कार्ति ने लिखा,...सनातन धर्म का अर्थ पदानुक्रमित जातिगत समाज है, तो लक्ष्मी ने कहा, नातन नफरत फैलाने वाले, जातिवादी हिंदुत्व का दूसरा नाम है, जिसकी उत्पत्ति उत्तर में हुई है। यक्ष प्रश्न है कि क्या ऐसी भाषा का उपयोग सभी मजहबी मान्यताओं व अवधारणाओं का आकलन करते समय किया जा सकता है? गत वर्ष का नूपुर शर्मा वाला प्रकरण

स्मरण कीजिए। तब नूपुर ने उन्हीं बातों को दोहराया था, जिसका उल्लेख अक्सर मुल्ला-मौलवी और जाकिर नाइक सरीखे विवादित इस्लामी विद्वान अपनी तकरीरों में करते हैं। फिर भी नूपुर को सांप्रदायिक घोषित कर दिया गया और उसका समर्थन करने वाले कन्हैया-उमेश को मौत के घाट तक उतार दिया गया। स्वयं नूपुर अपनी जान बचाने हेतु कड़ी सुरक्षा में भूमिगत है।

सच तो यह है कि उदयनिधि-कार्ति-लक्ष्मी के रूप में भारतीय समाज का एक वर्ग जिस संकीर्ण मानसिकता से अभिशप्त है, वह औपनिवेशिक शासन की देन है। जब अंग्रेज भारत आए, तब उन्होंने अपने राज को शाश्वत बनाने हेतु भारतीयों को भौतिक और बौद्धिक रूप से गुलाम बनाने की योजना पर काम प्रारंभ किया। अंग्रेजों ने भारतीय समाज की कमजोर कड़ियों को ढूंढकर ऐसी दूषित धारणाओं की स्थापना की, जिनसे स्वतंत्र भारत के कई स्वघोषित सेक्यूलरवादी आज भी जकड़े हुए हैं। द्रविड़ आंदोलन अंग्रेजों द्वारा निर्मित ऐसी ही एक धारणा है। इसकी उत्पति में ईस्ट इंडिया कंपनी के 1813 के चार्टर में जोड़े गए विवादित अनुच्छेद की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे अंग्रेज पादरियों और ईसाई मिशनरियों द्वारा अंग्रेज सरकार के सहयोग से स्थानीय भारतीयों का मतांतरण करने का रास्ता साफ हुआ था। इस मजहबी संयोजन से ब्राह्मणों के विरुद्ध वह मजहबी उपक्रम तैयार किया गया, जिसे स्थापित करने में 16वीं सदी में भारत आए फ्रांसिस जेवियर का बड़ा योगदान था। तब फ्रांसिस ने देश में रोमन कैथोलिक चर्च के मतांतरण अभियान में ब्राह्मणों को सबसे बड़ा रोड़ा बताया था। इसी प्रपंच के तहत चर्च के समर्थन से अंग्रेजों ने वर्ष 1917 में ब्राह्मण-विरोधी साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन किया, जिसे जस्टिस पार्टी (द्रविड़ कड़गम- डीके) नाम से भी जाना गया। तब इस षड्यंत्र में इरोड रामासामी नायकर पेरियार सबसे बड़े नेता बनकर उभरे, जिन्होंने न केवल 1947 में अंग्रेजों से मिली स्वतंत्रता पर शोक जताया, बल्कि अपने विकृत ब्राह्मण विरोधी अभियानों में खुलेआम सड़कों पर उतरकर हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों का अपमान भी करना शुरू कर दिया।

द्रमुक उसी हिंदू-विरोधी द्रविड़ कड़गम का अनुषंगिक-उत्पात है। यह दिलचस्प है कि 100 वर्ष पहले डीके जिन जुमलों का प्रयोग तत्कालीन कांग्रेस और गांधीजी के लिए करता था, अब वही शब्दावली कांग्रेस के समर्थन से भाजपा-आरएसएस के लिए आरक्षित हो गई है। क्या, बकौल आरोप, सनातन संस्कृति में जातिप्रथा या जातिगत भेदभाव को बढ़ावा मिलता है? भारत और सनातन धर्म एक-दूसरे के पूरक हैं। इस भूखंड पर सनातन परंपरा अपने चिर पुरातन, नित्य नूतन रूपी चिरंजीवी दर्शन के कारण अनादिकाल से विद्यमान है और इसके सबसे जीवंत प्रतिनिधि श्रीराम और श्रीकृष्ण हैं। उनका जीवन करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणास्रोत है। जब माता शबरी, जो आज की परिभाषा में दलित है और गैर-अभिजात्य वर्ग से है- पहली बार श्रीराम से मिलती हैं, तो वह अपनी स्थिति पर संकुचित अनुभव करती हैं। इस पर श्री रघुनाथ कहते हैं- जाति पांति कुल धर्म बड़ाई। धनबल परिजन गुन चतुराई।। भगति हीन नर सोइह कैसा। बिनु जल बारिद देखिअ जैसा।। इसका अर्थ यह है, 'मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूं। जात-पात, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, कुटुम्ब, गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य वैसा ही लगता है, जैसे जलहीन बादल। स्पष्ट है कि श्रीराम के लिए किसी व्यक्ति का जन्म, कुल, वैभव और सामाजिक स्तर नहीं, अपितु आचरण का महत्व है। इसलिए श्रीराम मांसाहारी गिद्धराज जटायु का, पितातुल्य बोध के साथ अंतिम-संस्कार करते हैं, तो पुलस्त्य कुल में जनित महाज्ञानी रावण का उसके अहंकार, काम, लोभ और भ्रष्ट आचरण के कारण वध करते हैं। अक्सर, जातियों को वर्ण की अभिव्यक्ति से जोड़कर देखा जाता है, जोकि मूर्खता है। श्रीभगवद्गीता में श्रीकृष्ण अर्जुन को संदेश देते हुए वर्ण को इस प्रकार परिभाषित करते हैं, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागश:। अर्थात 'मेरे द्वारा गुण और कार्य के आधार पर चार वर्णों की रचना की गई है।' स्पष्ट है कि सदियों से हिंदू समाज में व्याप्त अस्पृश्यता, सनातन वांग्मय से प्रेरित नहीं है। गांधीजी घोषित रूप से सनातनी हिंदू थे। सनातन संस्कृति पर उनके विचार थे, सनातन हिंदू धर्म संकीर्ण नहीं, उदार है। यह कुएं के किसी मेंढक की तरह घिरा हुआ नहीं है। यह मानवता का धर्म है।

हिन्द स्वराज्य

हिन्दुस्तान की दशा-2 (भाग-2)

गतांक से आगे...

प्रश्न- यह तो आपने इकतरफा बात कही। जैसे खराब लोग वहाँ जा सकते हैं वैसे अच्छे भी तो जा सकते है। वे क्यों रेलगाड़ी का पूरा लाभ नहीं लेते?

उत्तर- जो अच्छा होता है वह बीरबहूटी की तरह धीरे चलता है। उसकी रेल से नहीं बनती। अच्छा करने वाले के मन में स्वार्थ नहीं रहता। वह जल्दी नहीं करेगा। वह जानता है कि आदमी पर अच्छी बात का असर डालने में बहुत समय लगता है। बुरी बात ही तेजी से बढ़ सकती है। घर बनाना मुश्किल है, तोड़ना सहल है। इसलिए रेलगाड़ी हमेशा दुष्टता का ही फैलाव करेगी, यह बराबर समझ लेना चाहिए। उससे अकाल फैलेगा या नहीं, इस बारे में कोई शास्त्रकार मेरे मन में घड़ी भर शंका पैदा कर सकता है; लेकिन रेल से दुष्टता बढ़ती है यह बात जो मेरे मन में जम गयी है वह मिटने वाली नहीं है।

प्रश्न- यह बात मुझे ज्यादा समझनी होगी।

उत्तर- मैं जो कहता हूँ वह बिना सोचे-समझे नहीं कहता। एक-राष्ट्र का यह अर्थ नहीं कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं था; लेकिन हमारे मुख्य लोग पैदल या बैलगाड़ी में हिन्दुस्तान का सफर करते थे, वे एक- दूसरे की भाषा सीखते थे और उनके बीच कोई अंतर नहीं था। जिन दूरदर्शी पुरुषों ने सेतुबंध रामेश्वर, जगन्नाथपुरी और हरिद्वार की यात्रा ठहरायी, उनका आप की राय में क्या खयाल होगा? वे मूर्ख नहीं थे, यह तो आप कबूल करेंगे। वे जानते थे कि ईश्वर-भजन घर बैठे भी होता है। उन्होंने हमें सिखाया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन उन्होंने सोचा कि कुदरत ने हिन्दुस्तान को एक-देश बनाया है, इसलिए वह एक राष्ट्र होना चाहिए। इसलिए उन्होंने अलग-अलग स्थान तय करके लोगों को एकता का विचार इस तरह दिया, जैसा दुनिया में और कहीं नहीं दिया गया है। दो अंग्रेज जितने एक नहीं हैं उतने हम हिन्दुस्तानी एक थे और एक हैं। सिर्फ हम और आप जो खुद को सभ्य मानते हैं उन्हीं के मनमें ऐसा आभास (भ्रम पैदा हुआ कि हिन्दुस्तान में हम अलग-अलग राष्ट्र है। रेलवे कारण हम अपने को अलग राष्ट्र मानने लगे और रेल के कारण एक राष्ट्र का खयाल फिर से हमारे मन में आने लगा, ऐसा आप माने तो मुझे हर्ज नहीं है। अफीमची कह सकता है कि अफीम के नुकसान का पता मुझे अफीम से चला, इसलिए अफीम अच्छी चीज है। यह सब आप अच्छी तरह सोचिये। अभी आपके मन में और भी शंकाएँ उठेगी। लेकिन आप खुद उन सबको हल कर सकेंगे।

क्रमश: ...

सनातन मामले पर बैकफुट पर ही रहेगा विपक्ष

चंद्रभूषण

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और खेल एवं युवा मामलों के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने अपने एक भाषण में सनातन धर्म को लेकर जो कटुतापूर्ण बात कही, वह न केवल उनकी पार्टी डीएमके बल्कि समूचे द्रविड़ आंदोलन की स्थापित लाइन रही है। कोरोना वायरस और कुछ अन्य संक्रामक बीमारियों के ही क्रम में सनातन धर्म का भी नाम गिनाते हुए उन्होंने कहा कि इनका विरोध नहीं, उन्मूलन किया जाना चाहिए। अगले आम चुनाव के लिए धीरे-धीरे गर्मा रहे राजनीतिक माहौल में भाजपा ने इस मामले को डीएमके तक सीमित रखने के बजाय विपक्ष के इंडिया गठबंधन के खिलाफ मोड़ दिया, जो स्वाभाविक था। लेकिन कई गैर-भाजपा राजनेताओं और कर्ण सिंह जैसे गंभीर कांग्रेसी नेता ने भी शालीन ढंग से उदयनिधि के इस बयान पर आपत्ति जताई है।

द्रविड़ विचारधारा और सनातन धर्म को लेकर उसके दृष्टिकोण की तह में जाने से पहले युवा नेता उदयनिधि की इस सफाई पर भी एक नजर डाल ली जाए कि सनातन धर्म के उन्मूलन की बात कहकर उन्होंने किसी समुदाय के खिलाफ कोई आह्वान नहीं किया है। बहरहाल, इस सफाई से कुछ बातें साफ नहीं होतीं। मसलन यह कि सनातन धर्म या किसी और धर्म के बारे में कोई बात कही जाती है तो उसके साथ कई पहलू जुड़े होते हैं। एक तो उसे मानने वाले, जो बच्चे-बुजुर्ग, अमीर-गरीब, स्त्री-पुरुष कुछ भी हो सकते हैं और धर्म से उनके जुड़ाव का स्तर भी अलग-अलग हो सकता है। दूसरा, उस धर्म का ढांचा, जिसमें धर्म के व्याख्याकार और पूजापाठी से लेकर धर्मग्रंथ और धर्मस्थल, साथ में उस धर्म की परस्पर विरोधी धाराएं भी शामिल हैं। उदयनिधि ने धर्म के मानने वालों को लेकर एक सफाई जरूर पेश की है, लेकिन बाकी चीजों के बारे में कुछ नहीं कहा है।

द्रविड़ आंदोलन और इसके संस्थापक ईवी रामास्वामी 'पेरियार' की नास्तिक विचारधारा शुरू से हिंदू धर्म या सनातन धर्म को इसकी तमाम दार्शनिक बहसों समेत इसके सारे पहलुओं के साथ खारिज करती आई है। चाहे आर्यसमाज आंदोलन हो, चाहे विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन हो, या फिर गांधी का उदार सनातनी चिंतन, पेरियार ने आगे बढ़कर हर एक के खिलाफ हमला बोला और इन सब के दूसरे पहलू उजागर किए। और तो और, डॉ. भीमराव आंबेडकर ने जब अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो उनकी इस पहल को भी पेरियार ने ठीक नहीं समझा। आगे चलकर उनकी बात सही साबित हुई कि डॉ. आंबेडकर के बौद्ध हो जाने

का समाज पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उलटे भारत की सनातनी मुख्यधारा को उनके आंदोलन का असर सीमित करने में इससे थोड़ी और मदद मिल जाएगी।

यह सचमुच दिलचस्प है कि भारत में सनातन धर्म को लेकर परस्पर विरोधी नजरिया रखने वाली दो धाराओं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पेरियार के सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की स्थापना 1925-26 में थोड़ा ही आगे-पीछे हुई। यकीनन, पेरियार की चिंतन परंपरा की जड़ें तमिल इतिहास में काफी गहरी थीं, वरना भारत में एक खांटी नास्तिक सोच के साथ किसी राजनीतिक विचारधारा का इतने समय तक जिंदा रह जाना लगभग असंभव था। यहां एक और पहलू की ओर ध्यान दिलाना जरूरी है कि अपनी सारी तेजस्विता के बावजूद पेरियार अपने जीवनकाल के अंतिम बीस वर्षों में अपनी धारा के लिए ही अप्रासंगिक हो गए थे। इसका बड़ा कारण दक्षिण भारत और श्रीलंका के तमिल हिस्सों को मिलाकर अलग द्रविड़ राष्ट्र बनाने की उनकी मांग थी, जो उनकी राजनीति को आगे ही नहीं बढ़ने दे रही थी। फिर एक दिन अन्नादुरै ने पेरियार से अलग होकर डीएमके बना ली और इस धारा में उनका कद ज्यादा ऊंचा हो गया।

उदयनिधि के बयान के सिलसिले में इस प्रकरण को याद करने का मकसद यह है कि लोकतांत्रिक राजनीति में अतिरेकपूर्ण बातें फायदा जरूर पहुंचाती हैं, लेकिन इसमें दूर तक वही चल पाता है जो एक स्तर पर पहुंचकर व्यावहारिकता के साथ अपना संतुलन बना पाता है। उत्तर भारत में परिवर्तनकामी धाराओं ने सनातन धर्म को समाप्त करने या सिरे से उसे खारिज करने का रास्ता नहीं अपनाया। पेरियार का बौद्धिक प्रभाव यहां भी दिखा, लेकिन वह कुछ व्यक्तियों या छोटे दायरों तक ही सीमित रहा। बिहार में जगदेव प्रसाद और उत्तर प्रदेश में ललई सिंह यादव का नाम इस सिलसिले में आज भी इज्जत से लिया जाता है। लेकिन पिछड़ा आंदोलन का नेतृत्व उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर समाजवादियों के ही हाथ में रहा, जिनके वैचारिक नेता डॉ. राममनोहर लोहिया का नजरिया सनातन धर्म में सुधार का था। इसी के अनुरूप उन्होंने साधुओं का संगठन बनाया और 'राम, कृष्ण और शिव' तथा 'सीता और द्रौपदी' जैसे निबंधों के जरिये मिथकीय और महाकाव्यात्मक चरित्रों को नए अर्थ दिए।

दुर्भाग्यवश, सुधार का यह एजेंडा भी 1960 के दशक में संविद सरकारों के गठन के बाद से न सिर्फ सोशलिस्टों ने बल्कि उत्तर भारत की सारी राजनीतिक धाराओं ने छोड़ दिया। और तो और, दहेज हत्या और दलितों के गांव जला देने जैसे मुद्दे भी एक लंबे अर्से से भारतीय राजनीतिक मुख्यधारा के एजेंडे से बाहर जा चुके हैं। इससे पेरियार की कही हुई यह बात सही लगने लगती है कि सनातन धर्म के भीतर सुधार की बात कुछ निहित स्वार्थी लोग अपना कोई मकसद साधने के लिए ही करते हैं, क्योंकि जाति और लिंग, दोनों ही प्रश्नों पर इसकी नींव अन्याय और असमानता पर टिकी है। गांधी ने इस समझ को बदलने के लिए दशकों लगाए, लेकिन कितना इसे बदल पाए, हमारे सामने है।

भारत के विपक्षी दल कह रहे हैं कि सत्तारूढ़ भाजपा अपनी विफलताएं छिपाने के लिए ही मामले को हवा दे रही है। अपनी अगली बैठक में वह डीएमके नेताओं को धार्मिक मामलों पर संभल कर बोलने के लिए कह सकती है, जैसा अबतक मुस्लिम विपक्षी नेताओं से कहा जाता रहा है। लेकिन भारत जैसे देश में विपक्ष की कोई जमीनी राजनीति सांस्कृतिक मुद्दों को पूरी तरह से किनारे करके ज्यादा आगे नहीं जा सकती। उदयनिधि का सनातन धर्म को संक्रामक बीमारी बताना बहुत बड़ी आबादी की भावनाओं को चोट पहुंचाता है। लेकिन जो लोग, जो समुदाय धर्म से जुड़े जाति, लिंग और संप्रदाय के उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं, उनका पक्ष बड़े राजनीतिक धरातल पर उठाने के लिए एक न्यायसंगत मुहावरा जरूर खोजा जाना चाहिए।

एक देश, एक चुनाव राष्ट्रीय हित में उठाया गया कदम

सुरेश हिंदुस्तानी

वर्तमान में भारत में ऐसे कई कारण हैं, जो राष्ट्रीय विकास में बाधक बन रहे हैं। इसमें एक अति प्रमुख कारण बार-बार चुनाव होना है। देश में होने वाले चुनावों के दौरान लगने वाली आचार संहिता के चलते सरकार का कामकाज भी प्रभावित होता है। हमारे देश में किसी न किसी राज्य में हर वर्ष चुनाव के प्रक्रिया चलती रहती है। चुनाव के दौरान संबंधित सरकार कोई बड़ा निर्णय नहीं ले सकती। चुनाव होने के कारण राजनीतिक दल हर साल केवल चुनाव जीतने की योजना ही बनाते रहते हैं। इस कारण देश के उत्थान के बारे में योजना बनाने या सोचने का उतना समय भी नहीं मिल पाता, जितना सरकार का कार्यकाल होता है। इसलिए वर्तमान में जिस प्रकार से एक साथ चुनाव कराने की योजना पर मंथन चल रहा है, वह देश को उत्थान के मार्ग पर ले जाने का एक अभूतपूर्व कदम है। अभी केंद्र सरकार ने देश में एक साथ चुनाव कराने के बारे में प्राथमिक कदम उठाकर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इसके लिए एक समिति भी बनाई है, जो देश के राजनीतिक दलों और आम जनता से इसके हित और अनहित के बारे में विमर्श करेगी। जब सब ओर से सकारात्मक रुझान मिलेगा, तब यह धरातल पर उतारा जाएगा। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या एक साथ चुनाव कराया जाना उचित है? यकीनन इसका उत्तर यही होगा कि यह ठीक कदम है। लेकिन देश में कुछ राजनीतिक दल संभवत: इसकी गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं। इस कदम को संकुचित राजनीति के भाव से देख रहे हैं। अगर यह देशभाव के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमें यह कदम अच्छा ही लगेगा। वर्तमान में केन्द्र सरकार, चुनाव आयोग इस बारे में गंभीरता पूर्वक चिंतन कर रहा है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने एक बार अपने अभिभाषण में भी एक साथ चुनाव कराए जाने पर जोर दिया था। पूर्व राष्ट्रपति ने स्पष्ट कहा था कि बार-बार होने वाले चुनावों से विकास में बाधा आती है, ऐसे में देश के सभी राजनीतिक दलों को एक साथ चुनाव कराने के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। सच कहा जाए तो एक साथ चुनाव कराया जाना राष्ट्रीय चिंता का विषय है, जिसे सभी दलों को सकारात्मक दृष्टि से लेना होगा। हम यह भी जानते हैं कि देश के स्वतंत्र होने के पश्चात लम्बे समय तक एक साथ चुनाव की प्रक्रिया चली, लेकिन कालांतर में कई राज्यों की सरकारें अपने कार्यकाल की अवधि को पूरा नहीं कर पाने के कारण हुए मध्यावधि चुनाव के बाद यह क्रम बिगड़ता चला गया और चुनाव अलग-अलग समय पर होने लगे। इसके कारण देश में सरकारी कामकाज की प्रक्रिया तो बाधित होती ही है, साथ ही सरकारी कामकाज को लेकर सक्रिय रहने वाले सरकारी अधिकारी और आम जनता भी ऐसी बाधाओं के चलते निष्क्रियता के आवरण को ओढ़ लेते हैं। यह भी काम में रुकावट का कारण बनती है। इन सभी कारणों के निदान के लिए देश में एक साथ चुनाव कराने के विषय पर सभी राजनीतिक दलों के बीच संवाद बढ़ना चाहिए और इस बारे में आम सहमति बनायी जानी चाहिए। केंद्र सरकार की मंशा स्पष्ट है, लेकिन विपक्षी राजनीतिक दल इस बारे में क्या राय रखते हैं, यह अभी तक सामने नहीं आ पाया है। हालांकि देश हित के मुद्दे पर विपक्षी राजनीतिक दलों को भी इस बारे में सरकार के रुख का पूरी तरह से समर्थन करना चाहिए। एक साथ चुनाव होने से देश में विकास की गति को समुचित दिशा मिलेगी, जो बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि देश में बार-बार चुनाव होने से जहां राजनीतिक लय बाधित होती है, वहीं देश को आर्थिक बोझ भी झेलना पड़ता है।

नए जिलों पर सवार चुनावी जीत की उम्मीदें और सियासी दांव

अजय बोकिल

मध्यप्रदेश में भाजपा की सत्ता में वापसी का एक और चुनावी टोटका धड़ाधड़ नए जिलों की घोषणा है। इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रिकॉर्ड बनाने की स्थिति में हैं। बीते 40 दिनों में उन्होंने राज्य में 4 नए जिलों की घोषणा कर दी है। सतना जिले से अलग कर मैहर को नया जिला घोषित करना इसकी ताजा कड़ी है और चूंकि विधानसभा चुनाव घोषित होने और आचार संहिता लगने में अभी करीब एक माह का समय बाकी है, इसलिए चार-पांच और नए जिले घोषित हो जाएं तो आश्चर्य नहीं। मैहर को मिलाकर मप्र में अब कुल 56 जिले हो गए हैं। इनमें से 53 का विधिवत गठन हो चुका है और बाकी 3 गठन की प्रक्रिया में हैं। इतने जिलों के साथ मध्यप्रदेश अब आकार के साथ-साथ जिलों की संख्या के मामले में भी देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। देश में सबसे ज्यादा 72 जिले उत्तर प्रदेश में हैं तो सबसे कम 2 जिलों वाला राज्य गोवा है। भारतीय प्रशासनिक प्रणाली में जिले का महत्व इसलिए है कि यह देश में त्रिस्तरीय प्रशासन प्रणाली की केन्द्र व राज्य के बाद तीसरी और जमीनी क्रियान्वयन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, इसीलिए जिला कलेक्टर को इतनी शक्तियां दी गई हैं कि वो एक अर्थ में 'जिले का मालिक' ही होता है, इसीलिए हर आईएएस अधिकारी की मंशा यही होती है कि वो कम से कम एक बार तो जिले का कलेक्टर बनकर सत्ता और प्रशासनिक क्षमता दिखाने का सुख भोगे। वैसे किसी भी राज्य में जिलों का गठन मुख्यत: एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह अधिकृत है। वैसे 'नए जिलों की राजनीति' करने वाले शिवराज अकेले मुख्यमंत्री नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने तो पांच साल में 17 नए जिले बना दिए हैं। जिलों की संख्या के लिहाज में राजस्थान का नंबर देश में तीसरा है। यही चाल कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी चली है। उन्होंने पिछले पांच सालों में राज्य में 5 नए जिले बनाएं हैं, जिससे छत्तीसगढ़ जैसे अपेक्षाकृत छोटे राज्य में भी जिलो की संख्या बढ़कर अब 33 हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि राज्य में जो नए जिले बनाए गए हैं, उनमें से ज्यादातर के नाम किसी रेलगाड़ी की तरह हैं। मसलन मोहला- मानपुर- अंबागढ़ चौकी जिला। खैरागढ़-छुईखदान-गडई जिला या फिर मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला। इसका आम बोलचाल में प्रयोग कैसे होता होगा यह सोचने की बात है। नए जिले बनाने का असली मकसद यही है कि प्रशासन की पहुंच लोगों तक आसानी से हो सके और उसके माध्यम से सरकारी कामकाज सुचारू और दुरुत गति से चल सके, क्योंकि नया जिला बनने से संचार सुविधाएं भी अपने आप बढ़ती हैं। हालांकि आजकल नया जिला बनाना राजनीतिक फैसला ज्यादा बन गया है, क्योंकि अलग जिला बनाना और उसके लिए आंदोलन कर लोगों को एकजुट करना सीधे राजनीतिक लाभांश देने वाली प्रक्रिया है। इसमें दो राय नहीं कि आकार में विशाल होने के कारण मप्र के कई जिलों में जिला मुख्यालय से गांवों कस्बों की दूरियां काफी हैं। स्थानीय लोगों का ज्यादातर काम जिला मुख्यालय से ही पड़ता है और जिला मुख्यालय मीलों दूर होने से लोगों को असुविधा होती है। एक अनुभव यह भी है कि छोटे जिलों में प्रशासन का आम लोगों से ज्यादा आसानी से संपर्क हो पाता है और कानून व्यवस्था और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में भी आसानी होती है।

राजस्थान में भाजपा की परिवर्तन यात्रा

रमेश सर्राफ धमोरा

राजस्थान भाजपा में आपसी गुटबाजी खुलकर उजागर हो रही है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित सभी बड़े नेता अपने को फ्रंट में लाने के प्रयास में लगे हुये हैं। वसुंधरा समर्थकों को मानना है कि उनके पास अपनी ताकत दिखाने का अब अंतिम अवसर है। यदि इस बार चूक गए तो फिर मुख्य धारा की राजनीति में पिछड़ जाएंगे। वसुंधरा समर्थक कई विधायकों को तो इस बात का डर भी सता रहा है कि यदि मैडम राजनीतिक रूप से कमजोर होती हैं तो उनकी टिकट भी खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए वसुंधरा के सभी समर्थक जोर दे रहे हैं कि मैडम पार्टी आलाकमान से दो टूक बात करें।

पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी राजस्थान में भाजपा की फूट को लेकर पूरी तरह सतर्क है। भाजपा आलाकमान जानता है कि राजस्थान भाजपा में सभी नेताओं के अपने-अपने गुट बने हुए हैं। जिसके चलते सभी एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में लगे हुए हैं। भाजपा ने अपने प्रादेशिक नेताओं की आपसी खींचतान के चलते ही प्रदेश के चार क्षेत्रों में निकली जाने वाली परिवर्तन संकल्प यात्रा का नेतृत्व किसी भी बड़े नेता को नहीं सौंपा है। भाजपा ने चारों यात्राओं का नेतृत्व सामूहिक रूप से करने का निर्णय लिया है। ताकि यात्रा के बहाने कोई नेता खुद को बड़ा नहीं दिखा सके। यात्रा के संयोजन की जिम्मेदारी पार्टी ने दूसरी पंक्ति के नेताओं को दी है ताकि बिना गुटबाजी के यात्राओं का समापन हो सके।

ऐसे में अब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया सहित किसी भी अन्य नेता के बीच मुख्यमंत्री बनने की होड़ खत्म हो गई है। अब अगर पार्टी सत्ता में आती है तो शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। भाजपा की ओर से निकाली जाने वाली परिवर्तन यात्रा को लेकर चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण पंचारिया ने बताया कि भाजपा प्रदेश में आगामी दो सितंबर से

परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर चुकी है। यह यात्रा चार अलग-अलग स्थानों और दिशाओं से प्रदेश भाजपा के सामूहिक नेतृत्व में 8,982 किलोमीटर का सफर तय कर प्रदेश की 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। परिवर्तन यात्रा के दौरान किसान चौपाल, युवा मोटरसाईकिल रैली, महिलाओं की बैठक और दलित चौपालें भी आयोजित की जा रही हैं।

पहली परिवर्तन संकल्प यात्रा दो सितंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंबौर सवाईमाधोपुर से प्रारंभ हुई। जिसमें भाजपा का प्रदेश नेतृत्व मौजूद रहा। दूसरी परिवर्तन यात्रा तीन सितंबर को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बेणेश्वर धाम डूंगरपुर से प्रारंभ हुई। तीसरी परिवर्तन यात्रा चार सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में रामदेवरा जैसलमेर से प्रारंभ हुई। यह यात्रा 18 दिनों में 2574 किलोमीटर चलकर जोधपुर संभाग, अजमेर व नागौर जिले की कुल 51 विधानसभा क्षेत्रों में जायेगी। चौथी परिवर्तन यात्रा पांच सितंबर को केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में गोगामेडी हनुमानगढ़ से प्रारंभ हुई। यह यात्रा 18 दिनों में 2128 किलोमीटर चलकर बीकानेर संभाग, झुंझुनू, सीकर और अलवर जिले की कुल 50 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। इस यात्रा का संयोजक पूर्व केन्द्रीय मंत्री सीआर चौधरी व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण बगडी को सह-संयोजक बनाया गया है।

इन सभी यात्राओं के लिए एक टोली का गठन किया गया है। जिसमें मीडिया, सोशल मीडिया, आईटी एंव प्रचार-प्रसार सभा के प्रमुख बनाए गए हैं। प्रदेश की गहलोत सरकार के राज में भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण एवं कुशासन के कारण प्रदेश की जनता त्रस्त है। इसलिए कांग्रेस की इस जनविरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता ने संकल्प ले लिया है। विधानसभा चुनाव से पहले निकाली जा रहीं भाजपा की चारों परिवर्तन यात्राओं को केंद्रीय स्तर के नेताओं ने रवाना किया। भाजपा ने किसी एक चेहरे को इन यात्राओं की जिम्मेदारी नहीं दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि प्रदेश स्तर की यात्राओं में भाजपा आलाकमान ने किसी भी स्थानीय नेता को जिम्मेदारी क्यों नहीं दी? इसका मुख्य कारण कारण पार्टी में व्याप्त गुटबाजी को माना जा रहा है। किसी एक नेता के चेहरे को आगे करने से पार्टी के अन्य नेता नाराज हो सकते हैं। इससे बचने के लिए पार्टी ने यह कदम उठाया है। पार्टी आलाकमान नहीं चाहता कि चुनाव से पहले किसी तरह के मतभेद सामने आएं।

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी आलाकमान ने उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है। इससे राजे और उनके समर्थक नाराज बताए जा रहे हैं। परिवर्तन यात्रा को लेकर भी पार्टी ने राजे को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है। इससे पहले हुए भाजपा के कई कार्यक्रमों में राजे शामिल नहीं हुईं थीं। कुछ दिनों पूर्व गंगापुरसिटी में अमित शाह के कार्यक्रम में भी वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुयीं जबकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। हालांकि वह परिवर्तन यात्रा में शामिल हुईं।

भाजपा आलाकमान विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरा बना रहा है। मगर पार्टी के अंदरखाने मची जंग पर अभी तक नियंत्रण नहीं कर पाया है। वसुंधरा राजे के दो बार मुख्यमंत्री रहने से उनका आज भी लोगों पर काफी प्रभाव है। यदि पार्टी आलाकमान चुनाव में उनकी उपेक्षा करेगा तो यह पार्टी के लिए घाटे का सौदा भी साबित हो सकता है। फिलहाल वसुंधरा राजे अभी चुप्पी साधे हुए हैं तथा सही समय का इंतजार कर रही हैं। अंदर खाने वसुंधरा राजे ने अपनी राजनीति का अगला प्लान तैयार कर रखा है। इसलिए वह अपने धुर विरोधियों से मिलकर उनसे राजनीतिक मतभेद समाप्त कर रही हैं।

राजनीतिक दलों की नजर में बढ़ता महिला वोटरों का महत्व

सिद्धार्थ शंकर गौतम

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की अधिकृत घोषणा अभी होना शेष है किन्तु भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस तक ने आधी आबादी को अपने पक्ष में करने हेतु घोषणाओं के पिटारे खोल दिए हैं। और घोषनाएं भी क्यों न हों? आखिरकार मध्य प्रदेश में 48.20 प्रतिशत वोटर महिला हैं और यही आधी आबादी अब सत्ता बनाने बिगाड़ने के खेल की वजीर बन गई हैं। एक ओर जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिलाओं के लिए लाड़ली बहना योजना लेकर मैदान में हैं वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सत्ता में आने के बाद नारी सम्मान योजना लागू करने का वादा किया है। वर्तमान में प्रदेश की महिलाओं को लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं जिसे 10 अक्तूबर, 2023 से प्रतिमाह पहले 1,250 रुपए और बाद में 1,600 रुपए करने की घोषणा की गई है। अंतत: प्रत्येक पात्र महिला को 3,000 रुपए प्रतिमाह दिये जाने का प्रस्ताव है।

सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2023-24 में प्रदेश की भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के मद के लिए कुल 1 लाख 2 हजार 976 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जिसके अंतर्गत लाड़ली बहना योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 660 करोड़ रुपए, लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपए, कन्या विवाह एवं निकाह योजना के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा शिवराज सरकार ने महिलाओं को सावन में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा भी किया गया है जिसके अंतर्गत सरकार गैस एजेंसियों से जानकारी लेकर महिलाओं के खाते में 600 रुपए ट्रांसफर करेगी।

वहीं कांग्रेस के 11 वचन वाले चुनावी घोषणा पत्र को देखें तो उसमें भी आधी आबादी को खासा महत्त्व दिया गया है। 27 अगस्त, 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार बनने पर महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, मुफ्त स्कूली शिक्षा जैसे वादे किए हैं। राजनीतिक शक्ति के तीसरे केंद्र के रूप में स्वयं को स्थापित करने में जुटी आम आदमी पार्टी भी महिलाओं को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। प्रदेश में पार्टी की एकमेव महापौर भी महिला हैं अत: उनका चेहरा आगे कर महिलाओं को जोड़ने की कवायद जारी है।

इन सबके अलावा पुलिस और दूसरी भर्तियों में महिलाओं का आरक्षण 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करना, शिक्षकों के पदों पर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण, बहनों की स्कूल फीस माफ, पात्र महिलाओं को आजीविका मिशन के माध्यम से लोन जैसे वादों ने राजनीति में बढ़ती महिला वोट की ताकत का एहसास करवा दिया है।

दरअसल, बीते दशकों से महिलाओं के वोटों ने कई सरकारों को बनाया-बिगाड़ा है। राजनीतिक गुणा-भाग

में अपना आर्थिक व घरेलू हित ढूंढती महिलाओं में अब जागृति आई है और कौनसा राजनीतिक दल उन्हें लाभ देने के साथ ही उनकी किचन का आर्थिक भार कम कर रहा है, उन्हें बखूबी समझ में आ रहा है। वे मतदान के दिन घर की देहरी लांघ कर अपनी हितैषी सरकार चुन रही हैं।

मध्य प्रदेश की ही बात करें तो चुनाव आयोग के अनुसार, प्रदेश में 5.39 करोड़ मतदाता हैं जिनमें से 2.60 करोड़ यानी 48 प्रतिशत से अधिक महिला मतदाता हैं। पिछले पांच वर्ष में प्रदेश में 35 लाख से अधिक मतदाता बढ़े हैं जिनमें 19 लाख महिला मतदाता हैं। वहीं प्रदेश के 40 जिले तो ऐसे हैं जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है।

चुनाव आयोग के अनुसार, 2013 के विधानसभा चुनाव में 70 प्रतिशत महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था जबकि 2018 में यह आंकड़ा बढ़कर 74 प्रतिशत हो गया है जिससे स्पष्ट है कि महिलाएं इस बार भी बढ़-चढ़कर मतदान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगी। इन सबसे इतना तो तय है कि राजनीतिक दल भले ही महिलाओं को टिकट देने के मामले में कंजूसी बरतें, 33 प्रतिशत आरक्षण पर कन्नी काटें लेकिन वोटों के लिए उनकी अनदेखी तो नहीं कर सकते।

हाल ही में, रक्षाबंधन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की छूट महिलाओं को सीधे तौर पर प्रभावित करने का उपक्रम है। कुछ ऐसा ही वादा विपक्षी दलों का गठबंधन भी कर रहा है। राजस्थान में तो गहलोत सरकार ने 500 रुपए में सिलेंडर देना भी शुरू कर दिया है गोयाकि महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी दलों के बीच एक होड़ लगी है।

नवंबर, 2021 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा था कि भारतीय लोकतंत्र ने पहले लोकसभा चुनावों के बाद से एक उल्लेखनीय दूरी तय की है और आज सात दशक और 17 आम चुनावों के बाद, मताधिकार का प्रयोग करने में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक हो गई है। उन्होंने यह भी इंगित किया कि भारत में 1971 के चुनावों के बाद से महिला मतदाताओं में 235.72 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि देखी गई है। उनके अनुसार, 2019 के आम चुनाव में अलग महिला बूथ स्थापित किए गए और 27,527 ऐसे बूथ महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए, जहां मात्र महिलाओं ने मतदान किया।

महिलाओं के बढ़ते मत प्रतिशत के बाद एक प्रश्न भी उठता है कि क्या महिलाओं की राजनीतिक चेतना वास्तव में बढ़ी है? क्या राजनीति ने उन्हें उचित हिस्सेदारी दे दी है? इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिहेवियरल सोशल एंड मूवमेंट साइंस में छपे एक अध्ययन के अनुसार, यद्यपि महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है किन्तु महिला उम्मीदवारों की संख्या अभी भी निराशाजनक ही है। राजनीतिक दल भी महिलाओं को बराबरी का मौका देने का दिखावा करते हैं जबकि उन्हें मत मिलने के अनुपात में उन्हें राजनीतिक रूप से अवसर भी देना चाहिए।

बढ़ती राजनीतिक समझ और पंचायत चुनाव में प्राप्त आरक्षण ने महिलाओं को राजनीतिक रूप से अधिक मुखर कर दिया है जिसके चलते सभी राजनीतिक दल उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हैं। इसके लिए राजनीतिक दलों द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ महिलाओं के जरिए पूरे परिवार को मिल रहा है।

श्रीकृष्ण की छवि से मिलती हैं सीख

जानिए कृष्ण के स्वरूप और इसका महत्व

देशभर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। जन्माष्टमी को गोकुलाष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्रीकृष्ण ने माता देवकी के गर्भ से पृथ्वी पर जन्म लिया था।

यही कारण है कि हर साल इस दिन भक्त श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। श्रीकृष्ण का जीवन अद्भुत और अलौकिक रहा। उन्हें भगवान विष्णु का आठवां अवतार माना जाता है।

कृष्ण की लीलाएं, गाधाएं और स्वरूप भी अद्भुत हैं। श्रीकृष्ण की छवि जब हमारे मन में आती है तो सुंदर सांवला रूप, माथे पर मोरपंख, हाथ में बांसुरी और पीतांबर धारण किए कान्हा नजर आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि, भगवान कृष्ण का स्वरूप केवल दिखने में मोहक नहीं है, बल्कि इनसे हमें जीवन में सीख भी मिलती है। वास्तव में श्रीकृष्ण का मनोहर रूप हमें सफल जीवन जीना सीखाता है। लेकिन इसे जानने के लिए आपको श्रीकृष्ण के स्वरूप को गहराई से समझने की जरूरत है।

श्रीकृष्ण की छवि से मिलने वाली प्रेरणा

मोरपंख : मां यशोदा श्रीकृष्ण के सिर पर हमेशा मोर मुकुट पहनाया करती थीं। कृष्ण का मोरमुकुट हमें यह संदेश देता है कि, जीवन में भी मोरपंख की तरह कई तरह के रंग हैं। सुख, दुख, सफलता,असफलता ही जीवन के कई रंग हैं। क्योंकि इन्हीं रंगों से मिलकर जीवन बना है। इसलिए जीवन के रंग से आपको जो कुछ भी प्राप्त हो इसे अपने माथे से लगाकर अंगीकार करें।

बांसुरी: भगवान श्रीकृष्ण के हाथों में बांसुरी होती है। कहा जाता है कि श्रीकृष्ण बहुत अच्छा बांसुरी बजाते थे। श्रीकृष्ण की बांसुरी यह संदेश देती है कि, जीवन में कैसी भी घड़ी आए लेकिन घबराना नहीं चाहिए बल्कि। क्योंकि भीतर में शांति हो तो जीवन सफल होता है।

वैजयंती माला: भगवान कृष्ण गले में वैजयंती माला पहनते थे, जोकि कमल के बीजों से बनती है। इसके दो अर्थ हैं, पहला ये कि कमल के बीच सख्त होते हैं और सख्त होने की वजह से ये आसानी टूटते नहीं, सड़ते नहीं व चमकदार बने रहते हैं। यह इस बात की सीख देते हैं कि, जीवन में सख्त होना भी जरूरी है। दूसरा अर्थ यह है कि, बीज की मंजिल भूमि होती है, जोकि हमें जमीन से जुड़कर रहने की सीख देती है।

पीतांबर: भगवान श्रीकृष्ण पीतांबर धारण किए होते हैं। पीला रंग संपन्नता का प्रतीक है। पीतांबर इस बात का संदेश है कि, पुरुषार्थ ऐसा करो कि संपन्नता स्वंय तुम्हारे पास चलकर आए।

कमरबंद: पीतांबर को ही भगवान ने कमरबंद भी बनाया है, जोकि इस बात का संदेश देता है कि, हमें हमेशा चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। जब भी धर्म के पक्ष में कोई कर्म करना पड़े तो हमेशा तैयार रहें।

मां यशोदा और राधा: भगवान श्रीकृष्ण की बाल्यवस्था की छवि में माता यशोदा उनके संग दिखाई देती है। वहीं अन्य छवियों में कृष्ण संग राधा भी है। कृष्ण की छवि में माता यशोदा या राधा के संग होने का अर्थ यह है, जीवन में स्त्रियों का महत्व होता है, जिसके बिना हर पुरुष अधूरा है। इसलिए उन्हें पूर्ण सम्मान दें और इस बात का भी ध्यान रखें कि स्त्री हमारी बराबरी में रहें, हमसे नीचे नहीं।

सुदर्शन चक्र: भगवान श्रीकृष्ण के सुदर्शन चक्र को बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है, जिसक तुलना अस्तित्व से की जाती है। यानी व्यक्ति का अस्तित्व ही उसके लिए सुदर्शन है। लोग आपके व्यक्तित्व को देखकर ही व्यवहार करते हैं। यही सुदर्शन की वजह से आपकी हर जगह जीत तय है।

गाय: भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा गाय होती है। कहा जाता है कि, भगवान को गाय-बछड़े बहुत प्रिय थे और वो इनके संग खेला करते थे। श्रीकृष्ण कहते हैं- गायो में मैं कामधेनू हूं, जो वास्तविक रूप में सारी इच्छा परिपूर्ण करती है। संसार में पृथ्वी और गो सेवा से बड़ा कोई उदार और क्षमादान देने वाला नहीं।

माखन-मिश्री के साथ कान्हा को पसंद है ये चीज

जानें जन्माष्टमी पर धनिया पंजीरी भोग का महत्व

जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है।

इस दिन भाद्रपद माह के कृष्ण कक्ष की अष्टमी तिथि पड़ रही है। इसी तिथि में भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था।

देशभर में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिलती है। मंदिर से लेकर घर-घर इस दिन कान्हा विराजते हैं और इनका पूजन किया जाता है। कहीं-कहीं तो विशाल झांकी भी निकाली जाती है। रात 12 बजे भगवान कृष्ण जन्म के बाद भक्त पूजा-पाठ कर भगवान को धनिया प्रसाद का भोग लगाते हैं, जिसे धनिया पंजीरी कहा जाता है।

धनिया पंजीरी का भोग लगाने के बाद इसे भक्तों के बीच प्रसाद स्वरूप वितरण किया जाता है। जन्माष्टमी में धनिया पंजीरी के भोग का विशेष महत्व होता है और इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। जानें आखिर क्यों जन्माष्टमी पर जरूरी है धनिया पंजीरी का भोग और घर पर कैसे तैयार करें भगवान कृष्ण का ये प्रिय भोग।

माखन-मिश्री के साथ कान्हा को पसंद है धनिया पंजीरी भी

जन्माष्टमी के पर्व में भगवान को कई तरह के फल, मिष्ठान, भोग या प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, जिसमें धनिया पंजीरी भी शामिल है और यह जन्माष्टमी का मुख्य प्रसाद है। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्रीकृष्ण को माखन-मिश्री अतिप्रिय है और वे बाल्यवस्था में पड़ोस के घरों की मटकी तोड़कर माखन मिश्री चुराकर खाया करते थे। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि श्रीकृष्ण को धनिया पंजीरी भी बहुत पसंद है। इसलिए जन्माष्टमी पर कृष्ण को धनिया पंजीरी का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि, धनिया पंजीरी का भोग लगाने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं।

कैसे तैयार करें धनिया पंजीरी भोग

धनिया पंजीरी का भोग तैयार करने के लिए दो कप धनिया का चूरा या पाउडर, एक कप कद्दूकस किया नारियल, एक चौथाई कप घी और थोड़े मेवे की जरूरत होगी। इसे बनाने के लिए एक साफ कड़ाही में मेवे डालकर भून लें। और किसी बर्तन में निकाल लें।

अब इसी कढ़ाई में घी डालकर धनिया पाउडर को मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक पकाएं। जब इसका रंग बदल जाए और सौंधी-सौंधी खुशबू आने लगे तब आंच बंद कर दें। इस मिश्रण को ठंडा होने दें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें भुने मेवे, सूखा नारियल और चीनी मिलाकर तुलसी का पत्ता डाल दें। कृष्णजी का प्रसाद तैयार करने के लिए तुलसी पत्ता डालना जरूरी होता है।

इस बात का विशेष ध्यान रखें कि, इस भोग बनाने के लिए पहले चूल्हे की साफ-सफाई कर लें और भोग को स्नान करने के बाद ही तैयार करें। भोग बनाने के बाद सबसे पहले इस श्रीकृष्ण को ही अर्पित करें। बाद में प्रसाद स्वरूप भक्तजनों या परिवार वालों में बांटे।

जन्माष्टमी पर घर में इस तरह सजाएं लड्डू गोपाल की झांकी, वास्तु दोष से मिलेगी मुक्ति

जन्माष्टमी को बाल गोपाल के स्वागत के लिए भव्य झाकियां सजाई जाती है। आप भी घर पर इन तरीकों से झांकी सजा सकते हैं, इससे वास्तु दोष भी दूर होगा।

मोरपंख – नंद के लाल बाल गोपाल का जन्मदिन मनाने के लिए घरों में अनेकों तरीके से झाकियां बनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी की झांकी में मोरपंख जरुर रखना चाहिए। मान्यता है इससे कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। मोरपंख को कान्हा के मुकूट, झेले के आसपास लगा सकते हैं।

बांसुरी – जन्माष्टमी पर झांकी में श्रीकृष्ण की मूर्ति के पास बांसुरी रखें। कहते हैं जो लोग बाल गोपाल के जन्मोत्सव पर घर में झांकी सजाते हैं उनके अच्छे दिन जल्द शुरु हो जाते हैं। भाग्योदय होता है, किस्मत के द्वार खुल जाते हैं। झांकी में बांसुरी रखने से घर में सुख-शांति आती है, वास्तु दोष का नाश होता है।

गाय और बछड़ा – श्रीकृष्ण को गाय से बहुत प्रेम है। ऐसे में उन्हें प्रसन्न करने के लिए झांकी में गाय और बछड़े की मूर्ति भी रखना चाहिए।

जन्माष्टमी झांकी की सही दिशा - घर के ईशान कोण में कान्हा जी की झांकी बनाएं। इससे वास्तु दोष से मुक्ति मिलता है। परिवार में प्रेम बढ़ता है।

वैजयंती के फूल – वैजयंती फूलों को बहुत सौभाग्यशाली माना गया है। जन्माष्टमी पर झांकी सजाने के लिए वैजयंती के फूलों का इस्तेमाल करें, मान्यता है इससे को वैजयंती के फूल चढ़ाने धन की कभी कमी नहीं रहती। कान्हा को वैजयंती के फूल बेहद प्रिय है।

जन्माष्टमी को इन मंत्रों के जाप से मिलेगा जीवन का हर सुख

जन्माष्टमी पूजा विधि

जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने वाले जातक कुण्ड्ली में क्रूर ग्रहों की शांति के लिए सुबह जल में काले तिल डालकर स्नान करें। फिर ब्रह्मा जी सहित पंचदेवों को नमस्कार करके पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन ग्रहण करें। हाथ में जल, गंध, पुष्प लें और व्रत का संकल्प ङ्कमम अखिल पापप्रशमनपूर्वक सर्वाभीष्ट सिद्धये श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत करिष्येफ मंत्र का जाप करते हुए लें। इसके बाद श्रीकृष्ण के बाल रूप की पूजा करें।

फिर शाम को मज्योत्सनापते नमस्तुभ्यं नमस्ते ज्योतिषामपते। नमस्ते रोहिणिकांत अघ्र्यं मे प्रतिग्रह्यताम।फ इस मंत्र को बोलते हुए दूध मिश्रित जल से चंद्रमा को अघ्र्य दें।

रात्रि में कृष्ण भगवान के जन्म से पहले ऊँ क्रीं कृष्णाय नमःफ मंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान का श्रृंगार कर धनिया मिश्रित सौंठ पंजरी का प्रसाद श्रीकृष्ण को अर्पित कर आरती करें। श्रीकृष्ण को दूध, दही, माखन, मिश्री, मेवे और फल बहुत पसंद हैं। इसलिए भोग में ये चीजें जरूर होनी चाहिए। त्व देवां वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेति। मंत्र के जाप के साथ भगवान कृष्ण का भोग लगाना चाहिए।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मंत्र

आज जन्माष्टमी के दिन के लिए कुछ मंत्र बते रहे हैं, जिसका जाप करने से आप अपने जीवन में अत्यधिक लाभान्वित होंगे। चाहे बात आपके सुख, ऐश्वर्य, नौकरी-बिजनेस, विद्या, बुद्धि, महालक्ष्मी का आशीर्वाद और समस्त बाधाओं से मुक्ति की हो। अगर आपकी चाह है तो जन्माष्टमी का दिन एक ऐसा शुभ दिन है, जिस दिन यदि आप सच्चे मन से मंत्रों का जाप करेंगे तो श्रीकृष्ण उन्हें स्वीकार करते है।

क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामलांगाय नमः- यह मंत्र श्रीकृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। इस मंत्र का जाप करने से नौकरी से संबंधित कोई भी परेशानी क्यों ना हो, सब स्वतः ही दूर हो जाती है।

ऊँ नमः भगवते श्रीगोविन्दायः- इस मंत्र का जाप करने से यश-ऐश्वर्य, सुख-समृद्धि की प्राप्ति के साथ बिजनेस में भी अपार सफलता मिलती है।

ऐं क्लीं कृष्णाय ह्रीं गोविंदाय श्रीं गोप-ीजनवल्लभाय स्वाहा ह्रसोंफ- इस मंत्र के जाप करने से माता सरस्वती का पूर्ण आशीर्वाद बना रहता है और बुद्धि व विद्या में वृद्धि होती है।

ङ्कऊँ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीकृष्णाय गोविंदाय गोप-ीजन वल्लभाय श्रीं श्रीं श्रींफ- मंत्र के जाप करने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होती है और व्यक्ति पूर्ण जोश के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है।

लीलादंड गोपीजनसंसक्तदोर्दण्ड बालरूप मेघश्याम भगवन विष्णो स्वाहाफ- इस मंत्र का जो व्यक्ति एक लाख जाप के साथ हवन करता है और हवन में तिल, अक्षत, शहद, घी और शक्कर के मिश्रण का प्रयोग करता है, उन्हें स्थिर लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है।

कृष्ण - गायों व दुर्बलों के संरक्षक

कृष्ण, सृष्टि के संरक्षक विष्णु, के प्रतिबिम्ब हैं, जो धर्म की रक्षा हेतु द्वापर युग में अवतरित हुए। एक अवतार का यही उद्देश्य होता है। जब भी सृष्टि में धर्म का पतन होता है तब उसकी स्थापना एवं सृष्टि के संरक्षण के लिए योगी तथा ऋषि मुनि यज्ञ द्वारा विष्णु जी की शक्ति का आह्वान करते हैं जिसके फलस्वरूप उस शक्ति की प्रतिक्रिया अवश्य होती है .....भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है-

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ।।4-7।।

अर्थात जब जब धर्म संकट में होता है, और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ।

यहाँ मैं एक बात पर ज़ोर देना चाहता हूँ की धर्म कोई मज़हब नहीं है और अंग्रेज़ी भाषा में भी इसका कोई पर्याय नहीं है। धर्म तो इस सृष्टि का आधार है, इसकी जीवन रेखा है जो इसे निरंतर चला रहा है। सूर्य का धर्म है पृथ्वी पर प्रकाश एवं गर्मी प्रदान करना, पेड़ का धर्म है पर्यावरण को शुद्ध करना तथा छाया एवं भोजन उप्लब्ध् कराना, मनुष्य का धर्म है- हर अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाना, निर्बलों की सहायता एवं रक्षा करना, तथा यह सुनिश्चित करना कि आसपास कोई भी भूखा न रहे। किन्तु आज मनुष्य अपने धर्म को भूल गया है, अपराध अपनी चरम सीमा पर हैं, गाय, कुत्ते, बंदर आदि जानवर भूख से मर रहे हैं, योग का व्यापारीकरण हो गया है, वेदों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, तथा प्रकृति के साथ अनुवांशिक संशोधन तथा संकरण जैसी प्रक्रियाओं द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है।

उदाहरण के तौर पर अभी हाल ही में दिल्ली के एक प्रख्यात हाट में एक गर्भवती गाय घायल पड़ी थी तथा उसके शरीर से बहुत लहू भी बह रहा था। ध्यान आश्रम के एक स्वयंसेवक ने उस गाय की मदद के लिए आस-पास के लोगों से सहायता मांगी लेकिन कोई आगे नहीं आया। फिर उसने फ़ोन करके एक वैन की व्यवस्था कर लोगों से उसे ट्रक में डालने की सहायता मांगी लेकिन तब भी कोई आगे नहीं आया, आखिरकार उस गाय की मृत्यु ही हो गयी..... अब आप उस बाज़ार में जाकर देखें तो गलियाँ और दुकानें त्यौहार की ख़ुशी में सुसज्जित हैं, दुकानदार बाल कृष्ण की मूर्तियाँ और सुनहरे मुकुट बेच रहे हैं क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है।

आश्चर्यजनक बात तो यह है कि कृष्ण गायों और दुर्बलों के रक्षक थे तथा हर अधर्म के विरुद्ध थे। हमारे ग्रंथों में उन्हें गोपाल कहा गया है, किन्तु आधुनिक काल में स्वयं को कृष्ण भक्त कहने वाले लोग वी आई पी दर्शनों की व्यवस्था तथा मूर्तियों और मंदिरों को सजाने में व्यस्त हैं और गाय जो कि कृष्ण को सर्वप्रिय थी, उसे बचाने का समय किसी के पास नहीं है।

मोक्ष पाने के लिए, भक्ति सबसे आसान मार्ग भी है और सबसे कठिन भी। जब भक्ति देवत्व की ओर महसूस होती है तो उसकी अभिव्यक्ति भी तरह - तरह की होती है । प्रत्येक भाव की अभिव्यक्ति साधक और उसकी साधना के स्तर का एक स्पष्ट संकेत है। अर्जुन भी कृष्ण भक्त थे और उन्होंने गौरक्षा हेतु अपना बारह वर्ष वनवास तथा एक वर्ष का अज्ञात वास दाँव पर लगा दिया था। यदि आप कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को व्यक्त करने के प्रार्थी हैं तो आपको चाहिए कि कृष्ण द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलें। इससे अधिक खुशी उन्हें और कोई चीज़ नहीं दे सकती क्योंकि विष्णु के सभी अवतार और शिव के सभी कार्यों का उद्देश्य गरीबों का उत्थान, अपने से कमज़ोर जीवों की रक्षा तथा पर्यावरण का संरक्षण रहा है।

यदि आप अपने इष्ट देव के चुने हुए कार्य नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ धार्मिक स्थलों पर जाकर फूल चढ़ाने और गायन करने से कुछ उपलब्ध नहीं होगा। यदि आप मंदिरों को सजाने में मग्न हैं जबकि उन्हीं मंदिरों के बाहर कूड़े के ढेर लगे हों और पशु-पक्षी व् जन -साध-ारण पीड़ा व् अत्याचार ग्रस्त हों तो मैं आश्वासन देता हूँ कि आप अपने इष्ट देव के आसपास भी नहीं हैं। फिर चाहे आपको अद्भुत वी आई पी दर्शन हो जाएँ या आपको अपने पसंदीदा मंदिर को फूलों और सुनहरे मुकुट से सजाने का मौका मिल जाये, सब निरर्थक है।

जन्माष्टमी भाद्रपद महीने की शुक्लपक्ष के आठवें दिन पर पड़ती है। यह दिन आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि इस दिन कृष्ण की शक्ति उस साधक के लिए आसानी से उपलब्ध होती है जो गुरु के सानिध्य में यज्ञ के माध्यम से उनके द्वारा दिखाए मार्ग का अनुसरण करता है। यह एक बहुत शक्तिशाली दिन है जब सनातन क्रिया और अष्टाँग योग की क्रियायों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है तथा साधकों के विचार भी शीघ्र फलित हो जाते हैं। यदि आप यज्ञ की शक्ति और विचारों को शीघ्र फलित करने की उसकी क्षमता तथा सूक्ष्म शक्तियों का अनुभव करना चाहते हैं तो आप ध्यान फाउंडेशन से संपर्क कर सकते हैं।

-अश्विनी गुरुजी
ध्यान आश्रम

संक्षिप्त समाचार

खरगे के आने पहले प्रभारी सचिव चंदन आएंगे आज

रायपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे 8 सितंबर को राजनांदगांव जिले के दौरे पर आ रहे है और उनके आने से पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं प्रदेश प्रभारी सचिव डॉ. चंदन यादव 7 सितंबर की सुबह राजधानी रायपुर पहुंच रहे है और दिनभर जीपीएम जिले के दौरे पर रहेंगे और शाम को राजनांदगांव के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रभारी सचिव चंदन 7 सितंबर को सुबह 8.30 बजे रायपुर से गौरेला जिला-जीपीएम के लिये रवाना होंगे। दोपहर 12.30 बजे सर्किट हाउस गौरेला में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव एवं शोभायात्रा में शामिल होंगे। दोपहर 2.30 बजे गौरेला से रायपुर के लिये रवाना होंगे। शाम 6.30 बजे रायपुर पहुंचकर राजनांदगांव के लिये रवाना होंगे। रात्रि 8.30 बजे राजनांदगांव पहुंचेंगे एवं रात्रि विश्राम राजनांदगांव में करेंगे। 8 सितबंर को ग्राम ठैकवा, राजनांदगांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यक्रम में भाग लेंगे। शाम 4 बजे राजनांदगांव से रायपुर के लिये रवाना होंगे। शाम 6 बजे सर्किट हाउस रायपुर पहुंचेंगे एवं रात्रि विश्राम रायपुर में करेंगे।

विस अध्यक्ष ने दी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर प्रदेशवासियों को बधाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी की समस्त प्रदेशवासियों को बधाई शुभकामनाएं देते हुए कहा कि, जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। डॉ. महंत ने कहा मैने अपने जीवन में श्री कृष्ण के उपदेश और पांच मंत्र ङ्क पहला मंत्र, शांत और धैर्य स्वभाव रखकर काम करना। दूसरा मंत्र, साधारण जीवन। तीसरा मंत्र, कभी हार न मानना। चौथा मंत्र, दोस्ती निभाना। पांचवा मंत्र, माता-पिता का हमेशा आदर करना इसे धनेश आत्मसात किया है। डॉ. महंत ने कहा, श्रीकृष्ण युगों-युगों से हमारी आस्था के केंद्र रहे हैं, वे कभी यशोदा मैया के लाल होते हैं, तो कभी ब्रज के नटखट कान्हा । जन्माष्टमी पर्व भगवान श्रीकृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर पूरे दिन व्रत का विधान है। जन्माष्टमी पर सभी 12 बजे तक व्रत रखते हैं। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण का अहम योगदान रहा, उन्होंने ही अर्जुन को धर्म और अधर्म के बारे में ज्ञान दिया था। भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को समस्त गीता का बोध ज्ञान करवाया था, गीता में जीवन का समस्त ज्ञान समाया हुआ है।

सिंगल नाम आधे से अधिक सीटों पर तय, गुरु का पेंच फंसा

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 90 विधानसभा में से आधे से अधिक सीटों पर लगभग नाम तय कर लिए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी में 8 सितंबर को इन नामों को रखा जायेगा और सेन्ट्रल इलेक्शन कमेटी में जाने के बाद संभवत:जल्द ही इसकी घोषणा भी हो जायेगी ताकि 21 सीटों की घोषणा करने वाली भाजपा पर दबाव बढ़ाया जा सके। कुछ सीटों पर दो-दो नाम का पैनल बना है वहां भी जल्द ही निपटारा हो जायेगा। सूत्र बता रहे हैं कि सभी मंत्रियों की टिकट भी तय है। केवल एक मंत्री रूद्र गुरु के नाम को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति है,क्योकि उन्होने नवागढ़ से चुनाव लडने की इच्छा जाहिर कर दी है,जबकि संसदीय सचिव गुरुदयाल यहां से वर्तमान में विधायक हैं। गुरु के नाम सामने आने की खबर पर संसदीय सचिव के समर्थक रायपुर पहुंचकर अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। उन्होने इस बात पर नाराजगी जाहिर की गुरु पहले आरंग से थे बाद में अहिवारा आ गए और अब नवागढ़ ..एकमात्र उनके लिए पार्टी के नियम कायदे क्या लागू नहीं होगे। यहां बताना यह भी जरूरी होगा कि एआईसीसी महासचिव वेणुगोपाल संकेत दे चुके हैं कि मंत्रियों को अपने ही विधानसभा सीट से चुनाव लडना है यदि नहीं तो वे टिकट से वंचित हो सकते हैं।

फुगड़ी और रस्साकस्सी के जिला स्तरीय छत्तीसगढिया ओलम्पिक में टेकारी विजेता

रायपुर। जिला स्तरीय छत्तीसगढिया ओलम्पिक के तहत खेले गये फुगड़ी व रस्साकस्सी के खेल में आरंग जनपद पंचायत के अधीन आने वाले ग्राम टेकारी (कुंडा) के प्रतिभागियों ने विजयश्री हासिल की। 40 + उम्र वर्ग के लिये आयोजित फुगड़ी प्रतियोगिता में जहां बुधारु साहू ने विजेता का खिताब जीता वहीं 0 से 18 उम्र के लिये आयोजित रस्साकस्सी में ग्राम के युवाओं की टीम विजेता बना। ज्ञातव्य हो शासन द्वारा छत्तीसगढिया ओलम्पिक का शुरुआत किया गया है जिसमें विभिन्न पारम्परिक छत्तीसगढिया खेल शामिल है। इस खेल में महिलाओं व पुरुषों को उम्र के हिसाब से 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग 0 से 18 वर्ष वाले, दूसरा वर्ग 18 से 40 उम्र का व तीसरा वर्ग 40 + उम्र वालों का। आयोजन ग्राम स्तर से शुरू हो ब्लाक के भीतर जोन व फिर ब्लाक उसके पश्चात जिला फिर संभाग और अंत में प्रदेश स्तर पर प्रतियोगिता का संपन्न होना है। रायपुर जिला के अंतर्गत आने वाले ब्लाक व नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत स्तर पर प्रतियोगिता संपन्न होने के बाद जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

प्रदेश में भाजपा निकालेगी परिवर्तन यात्रा

12 को जशपुरनगर से नड्डा, तो 16 सितंबर को दंतेवाड़ा से शाह करेंगे शुरुआत

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में दो परिवर्तन यात्रा निकलेगी। भाजपा परिवर्तन यात्रा की शुरुआत 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से करेगी। दूसरी यात्रा 16 सितंबर को जशपुरनगर से परिवर्तन यात्राओं का शंख फूंकेगी। इन यात्राओं में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जशपुरनगर से शुरुआत करेंगे। दूसरी यात्रा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा से करेंगे। यात्रा के समापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने एकात्म परिसर भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा से 12 सितंबर को और जशपुरनगर से 16 सितंबर को शुरू होगी। दंतेवाड़ा से शुरू होने वाली पहली यात्रा को मां दंतेश्वरी की पूजा-अर्चना के साथ केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे। दूसरी ओर जशपुरनगर से शुरू होने वाली यात्रा को कोरवा आराध्य देवी खुड़ियारानी की पूजा-अर्चना करके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे।

साव ने बताया कि पहली यात्रा दंतेवाड़ा से बिलासपुर तक 16 दिन में 1,728 किलोमीटर की का सफर तय करेगी। तीन संभागों के 21 जिलों तक पहुंचेगी। यात्रा के दौरान 45 आमसभाएं, 32 स्वागत सभाएं और पांच रोड शो होंगे। इसके संयोजक विधायक शिवरतन शर्मा व पूर्व मंत्री महेश गागड़ा होंगे। उनके साथ सहयोगी के रूप में निरंजन सिंहा और सचिन बघेल रहेंगे।

दूसरी यात्रा 16 सितंबर को जशपुरनगर से शुरू होगी। 12 दिन में दो संभागों के 14 जिलों के 39 विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचकर 1,261 किमी का सफर तय करेगी। इस दौरान 39 आमसभाएं, 53 स्वागत सभाएं और रोड शो होंगे। इसके संयोजक मोतीलाल साहू, सांसद गुहाराम अजगले, और प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव होंगे।

अरुण साव ने बताया कि यात्राओं का समापन 28 सितंबर को होगा। इस समापन यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। पहली यात्रा का नेतृत्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष साव खुद करेंगे। दूसरी यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल करेंगे। दोनों यात्राएं 87 विधानसभा क्षेत्रों की 2,989 किमी की यात्रा तय करेंगी। अरुण साव ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की ये परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में भ्रष्ट भूपेश सरकार की पोल खोलने का काम करेगी। बीजेपी ने जो यात्रा का रोडमैप बनाया है, उसके तहत यात्रा प्रतिदिन तीन विधानसभा के दौरे पर रहेगी। इसमें हर दिन एक बड़ी सभा का आयोजन किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रतिदिन छह स्वागत सभा, तीन छोटी सभा का आयोजन किया जाएगा।

परिवर्तन यात्रा में शिरकत करने 14 को रायगढ़ आएंगे पीएम मोदी

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से शुरु होगी और इस परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। वहीं 16 सितंबर को जशपुरनगर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को रायगढ़ के कोड़ातराई में आयोजित परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे जहां वे जनसभा को संबोधित करेंगे। परिवर्तन यात्रा का समापन बिलासपुर में होगा जिसमें भी प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे।

मतदान केंद्रों को लाइव देखेंगे रायपुर और दिल्ली के अफसर

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में ऐसा पहली बार है कि चुनाव का लाइव प्रसारण रायपुर और दिल्ली के अफसर देख सकेंगे। 50 प्रतिशत मतदान केंद्रों पर अफसर नजर रखेंगे। किसी भी जगह पर विवाद की स्थित बनी वहां तुरंत पहुंचेंगे। इस दौरान रायपुर कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने विधानसभा के परिपेक्ष्य में बलौदाबाजार विधानसभा के रायपुर जिले के अंतर्गत चुनाव की तैयारियों के संबंध में बैठक ली। यह बैठक तिल्दा जनपद पंचायत के सभाकक्ष में हुई। कलेक्टर ने कहा कि सभी सेक्टर के निर्वाचन और पुलिस अधिकारी अपने मतदान केन्द्रों का दौरा करें। पेयजल महिला-पुरूष शौचालय सहित आधारभूत व्यवस्थाएं का इंतजाम करें। यह देखे की किसी मतदान केन्द्र में पिछले चुनाव के समय में किसी प्रकार की गड़बड़ी या अशांति की स्थिति निर्मित ना हुई हो। 50 प्रतिशत मतदान केंद्रों से होने वाली लाइव प्रसारण के लिए मतदान केन्द्रों में नेटवर्क की जांच करें। डॉ भुरे ने कहा कि सभी सेक्टर ऑफिसर ईवीएम मशीन की संचालन की स्थिति और प्रक्रिया का अच्छी तरह परीक्षण कर लें, मतदान के समय में कोई भी ईवीएम के कारण कोई बाधा ना आए। सभी सेक्टर अधिकारी अपने मतदान दल के सदस्यों का नंबर अपने पास रखें। मोबाइल हर स्थिति में चालु रखें, इससे आपसी संपर्क बना रहे। उन्होंने कहा कि मतदान के एक दिन पहले देर शाम या रात को अपने सेक्टर के मतदान दलों से जाकर मुलाकात करें। कलेक्टर ने कहा कि मतदान शुरू होने से पहले अपने एरिया के सेक्टर ऑफिसर अपने मतदान केन्द्र में पहले और मॉकपोलिंग करवा लें। यह प्रकिया जितनी अच्छी होगी मतदान का कार्य भी उतना अच्छा होगा। डॉ भुरे ने कहा कि यह भी अच्छी तरह से सुनिश्चित करें कि सभी मतदान केन्द्रों में मॉकपोलिंग डिलीट हो जाए। उन्होंने कहा कि यह भी ध्यान रखें की रिजर्व ईवीएम सुरक्षित स्थान और सुरक्षा बलों के दायरे में रहे।

मंत्री श्रीमती भेंड़िया ने विभिन्न विकास कार्यों का किया भूमिपूजन

रायपुर। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया ने मंगलवार को बालोद जिले के डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। उन्होंने डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के ग्राम नारगी में नाली निर्माण, ग्राम बर्रापारा संजारी में सामुदायिक भवन निर्माण, ग्राम आलीवारा में मुक्तिधाम, संबलपुर में सामुदायिक भवन निर्माण का भूमिपूजन किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी मांगों एवं समस्याओं की जानकारी प्राप्त की और समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। श्रीमती भेंड़िया ने कहा कि ग्रामीणों की मांग के अनुरूप डौण्डीलोहारा क्षेत्र में लगातार विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने किसानों का कर्ज माफ कर उन्हें कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को धान, वनोपज सहित दलहन-तिलहन का बढ़ा मूल्य देकर अन्नदाताओं के मेहनत का सम्मान किया है। राज्य सरकार ने गांवों में आदर्श गौठान का निर्माण कर गौ संरक्षण की दिशा में अविस्मरणीय कार्य किया है। श्रीमती भेंड़िया ने कहा कि किसान समृद्ध होगा तो छत्तीसगढ़ भी बढ़ेगा।

मंत्री मरकाम ने 86 वनाधिकार पत्रों का किया वितरण

- कोण्डागांव जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में किया विकास कार्यों का भूमिपूजन-लोकार्पण
- 45 स्कूली छात्राओं को किया निःशुल्क साइकिल का वितरण

रायपुर। आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक विकास मंत्री श्री मोहन मरकाम ने आज कोण्डागांव जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने ग्राम कमेला, बड़ेकनेरा एवं धनपुर में 86 वन अधिकार पत्रों का वितरण किया। इनमें ग्राम पंचायत कमेला में 27, ग्राम पंचायत बड़ेकनेरा में 34 और ग्राम पंचायत धनपुर में 25 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र का वितरण किया। मंत्री श्री मरकाम ने शासकीय हाई स्कूल बफना में सरस्वती साइकिल योजना के तहत 45 स्कूली छात्राओं को निःशुल्क साइकिल का वितरण भी किया।

मंत्री श्री मरकाम ने विभिन्न ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण भी किया गया। उन्होंने ग्राम पंचायत बडेकनेरा में सीसी सड़क एवं नाली निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया। ग्राम पंचायत बफना में सीसी सड़क कार्य का लोकार्पण। मंत्री श्री मरकाम ने ग्राम पंचायत खड़का में सांस्कृतिक भवन का लोकार्पण, ग्राम पंचायत सिंगनपुर में पुलिया निर्माण कार्य का भी भूमिपूजन किया। ग्राम पंचायत धनपुर में उन्होंने पंचायत भवन निर्माण, पुलिया निर्माण, बाउण्ड्री वाल निर्माण, देवगुड़ी भवन निर्माण कार्य का लोकार्पण किया।

इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, शाकम्भरी बोर्ड के सदस्य श्री अनुराग पटेल सहित गांव के जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

जल जीवन मिशन: राज्य में 29.36 लाख से परिवारों को मिला घरेलू नल कनेक्शन

रायपुर। राज्य के ग्रामीण अंचलों में नि:शुल्क घरेलू नल कनेक्शन देने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए चलाए जा रहे इस अभियान के अंतर्गत 49 लाख 92 हजार 786 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिए जाने के विरूद्ध वर्तमान में 29 लाख 36 हजार 958 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसके साथ-साथ राज्य के 39 हजार 113 स्कूलों, 37 हजार 501 आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा 15 हजार 616 ग्राम पंचायत भवनों और सामुदायिक उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में टेप नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ का जांजगीर-चांपा जिला 01 लाख 45 हजार 967 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन देकर सबसे आगे है। इसी तरह रायपुर जिला 01 लाख 45 हजार 494, महासमुंद जिले में 01 लाख 45 हजार 290 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन देने में क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्रकुमार के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे इस जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य में प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन 55 लीटर के मान से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, इसके लिए सभी जिलों में कार्ययोजना तैयार कर तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। इस मिशन के तहत घरेलू नल कनेक्शन के अतिरिक्त स्कूल, उप-स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में भी रनिंग वाटर की व्यवस्था की जा रही है।

इसके साथ ही साथ राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी के अंतर्गत बनाए गए गौठानों में भी पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। उल्लेखनीय है कि सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी डॉ. एस. भारतीदासन एवं मिशन संचालक श्री आलोक कटियार द्वारा जमीनी स्तर पर राज्य में सिंगल विलेज स्कीम और मल्टी विलेज स्कीम और अन्य पेयजल योजनाओं सहित जल जीवन मिशन के कार्यों का क्रियान्वयन की लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है।

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूलों में हर वर्ग के बच्चों को मिल रही है निशुल्क उत्कृष्ट शिक्षा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की परिकल्पना अब साकार हो रही है। प्रदेश की स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी और हिंदी माध्यम स्कूल से राज्य के लाखों बेटे, बेटियों की जिन्दगी संवर रही है। इसका लाभ सुदूर वनांचल हो या मैदानी इलाका, प्रत्येक जगह देखने को मिल रहा है और आधुनिक शिक्षा की उजली तस्वीर देखने को मिल रही है। प्रदेश में वर्तमान सत्र 2023-24 में 377 अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय तथा 349 हिंदी माध्यम विद्यालय कुल 726 स्कूल संचालित किए जा रहे है। स्कूल में 1 लाख 70 हजार बच्चे अंग्रेजी माध्यम और 2 लाख 20 हजार बच्चे हिन्दी माध्यम में पढ़ाई कर रहे है। राज्य सरकार की पहल से आज सुदूर अंचल के बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में खेलने के लिए बढिया मैदान, आधुनिक प्रयोगशाला, पुस्तकालय, जैसी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन में

शुरू की गयी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों ने पालकों के आर्थिक बोझ को कम कर दिया है और पालकों के मन की चिन्ताएं दूर हो गई हैं। आज अंग्रेजी माध्यम स्कूल मैं पढ़ाई करके बच्चे अपनी प्रतिभा को बेहतर रूप में निखार रहे हैं। योजना ने आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के बच्चों का आत्मविश्वास और स्वाभिमान बढ़ाया है। अंग्रेजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थीयों ने बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट में अपना स्थान बनाया है। इन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, सुंदर भवन मार्डन पुस्तकालय, खेल मैदान, उत्कृष्ट प्रयोगशाला लैब आदि का बेहतर संचालन किया जा रहा है। जिससे प्रदेश में शासकीय विद्यालयों के प्रति बच्चों और पालकों के मन में लोकप्रियता बढ़ी है। स्वामी आत्मानंद विद्यालयों के संचालन से निर्धन गरीब वर्ग के बच्चों को उच्च गुणवत्ता के अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्राप्त होने से पालकों में बहुत उत्साह है। जिसके कारण सभी जगह से और भी आत्मानंद स्कूल खोले जाने की मांग लगातार हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में निजी और सरकारी शालाओं के बीच के अंतर को कम करने और बच्चों को बराबरी के अवसर देने के लिए यह योजना शुरू की है।

जांजगीर चांपा की राजनीति में हसदेव नदी की भूमिका

जांजगीर-चांपा। जांजगीर-चांपा को कोसा,कांसा और कंचन की नगरी कहा जाता है। चांपा के साथ जाज्वल्य देव की नगरी जांजगीर को मिलाकर जांजगीर चांपा विधानसभा को अस्तित्व में लाया गया। जिले की अगर बात करें तो यहां जांजगीर चांपा के अलावा अकलतरा विधानसभा सीट भी जिले के अंतर्गत आती है। जांजगीर चांपा विधानसभा में इस बार रणनीति तैयार करने के लिए राजनीतिक दल जुट चुके हैं।

आजादी के बाद से जांजगीर चांपा जिला का चुनावी समीकरण कुछ अलग ही रहा है। इस सीट मे संविधान निर्मात्री समिति के सदस्य ठाकुर छेदी लाल बैरिस्टर ने अपनी दावेदारी निर्दलीय प्रत्यशी के रूप मे की थी। लेकिन उन्हें कांग्रेस के रामकृष्ण राठौर ने पराजित कर दिया। इस सीट में ओबीसी वर्ग का दबदबा है। वैसे तो इस सीट में अनुसूचित जाति वर्ग के लोग अधिक है, लेकिन ओबीसी वर्ग जीत और हार का समीकरण तय करता है।इसके अलावा कुर्मी, कश्यप, साहू, राठौर जाति भी विधानसभा में है। अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के वोटर भी कम होने के बाद भी किसी भी प्रत्याशी के लिए दोनों वर्गों का मत अहम है।

जांजगीर चांपा विधानसभा में 2 लाख 3 हजार 535 मतदाता हैं। जिसमें से 99 हजार 7 सौ 76 महिला और 1 लाख 03 हजार 7 सौ 52 पुरुष मतदाता हैं।वहीं थर्ड जेंडर के 7 मतदाता शामिल हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में यहां का मतदान प्रतिशत 74 प्रतिशत तक था। जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था।

2018 का परिणाम

2018 विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय दलों के साथ-साथ स्थानीय और निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपना भाग्य आजमाया ।बीजेपी से नारायण चंदेल, कांग्रेस से मोतीलाल देवांगन और बसपा से व्यास कश्यप को मिलाकर 16 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे। जिसमें बीजेपी के नारायण चंदेल को 54 हजार 040 और कांग्रेस के मोतीलाल देवांगन को 49 हजार 852 मत मिले। करीबी मुकाबले में नारायण चंदेल ने मोतीलाल को 4188 मतों से हराया था। बसपा के व्यास कश्यप ने 33 हजार 505 मत हासिल किए थे।

आजादी के बाद से जांजगीर चांपा का चुनावी समीकरण कुछ अलग ही रहा है। इस सीट मे संविधान निर्मात्री समिति के सदस्य ठाकुर छेदी लाल बैरिस्टर ने अपनी दावेदारी निर्दलीय प्रत्यशी के रूप में। लेकिन उन्हें कांग्रेस के राम कृष्ण राठौर ने पराजित किया। इस सीट मे ओबीसी वर्ग का दबदबा है। वैसे तो इस सीट में अनुसूचित जाति वर्ग के लोग अधिक है। लेकिन ओबीसी वर्ग का अहम भूमिका रहती है। जिसमें कुर्मी, कश्यप, साहू, राठौर जाति प्रमुख रूप से अपना स्थान बनाये रखती है। अनुसूचित जन जाति और सामान्य वर्ग के वोटर भी कम होने के बाद भी राजनितिक क्षेत्र मे अपनी अच्छी पकड़ बनाये रखे है।

मुद्दे और समस्याएं

जांजगीर चांपा विधानसभा किसान बाहुल्य क्षेत्र है। क्षेत्र का 80 फीसदी भाग नहर के पानी पर निर्भर है ।किसान खरीफ फसल के तौर पर धान उगाकर और फिर उसे सरकार को बेचकर लाभ कमाते हैं ।लेकिन रबी की फसल में परिवर्तन ना करके वापस धान उगाते हैं ।दूसरी फसल के उत्पादन को सरकार नहीं खरीदती। सरकार के मूल्य निर्धारण नही करने से किसानों को दूसरी बार उगाई गई फसल का उचित दाम नहीं मिलता ।जिसे वो बिचौलियों की मदद से खुले बाजार में कम कीमत में बेचकर अपना खर्च निकालते हैं ।किसानों को अपनी इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार से कई बार ग्रीष्म कालीन फसल में धान के लिए नहर से पानी देने और फसल के उचित दाम की मांग की है ।जो अब तक पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा रोजगार की मांग, चिकित्सा, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था की मांग प्रमुख मुद्दे हैं ।वहीं शहरी क्षेत्रों में पेयजल की समस्या बनीं हुई है।

जांजगीर चांपा विधानसभा सभा सीट में हसदेव नदी आती है ।राजनीतिक दृष्टिकोण से ये नदी काफी अहम है। हसदेव नदी के बाई ओर चांपा नगर पालिका है और दायी ओर जांजगीर नगर पालिका। विधानसभा के हिसाब से बांई ओर कम वोटर है और दाएं हिस्से में अधिक मतदाता हैं ।कांग्रेस पिछले 25 साल से मोती लाल देवांगन को अपना प्रत्याशी बनाते आई है। वहीं बीजेपी लगातार नारायण चंदेल को चुनावी मैदान में उतार रही है। इसके अलावा नदी के दायी ओर जांजगीर नगर पालिका क्षेत्र में कांग्रेस से टिकट मांगने वालों की लम्बी लाइन है ।जिन्हें नदी के दूसरी ओर के वोटर्स को साधने में मुश्किल होती है ।यही हाल चांपा नगर पालिका क्षेत्र के लोगों के टिकट दावेदारों का भी रहता है।

केंद्र की योजनाओं को अपनी बताकर लूट रही है झूठी वाहवाही : सिद्दीकी

अल्पसंख्यक समुदाय प्रदेश सरकार के खिलाफ निर्णायक संघर्ष शुरू कर रहे हैं

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन बुधवार को राजधानी स्थित शहीद स्मारक भवन में आयोजित किया गया। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी सहित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद, वरिष्ठ विधायक व पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और भाजपा सरगुजा संभाग प्रभारी संजय श्रीवास्तव ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर मोर्चा के छत्तीसगढ़ प्रभारी मोहम्मद सद्दाम, प्रदेश प्रभारी डॉ. सलीम राज, सह प्रभारी आरिफ खान, राष्ट्रीय कार्य. समिति सदस्य व सूफी संवाद के राष्ट्रीय प्रभारी असलम खान, राष्ट्रीय सह प्रभारी इकबाल गोरी, श्रीमती नजमा अजीम, मुर्तजा वनक, अकरम कुरैशी, मिर्जा एजाज बेग, फादर फ्रेंकलिन, तौकीर रजा, अमरजीत छाबड़ा व लोकेश कावड़िया भी मंचस्थ थे। इस अवसर पर शेख आशिफ प्रदेश मंत्री भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगो ने भारतीय जनता पार्टी में अपनी सदस्य ली।

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से कार्ययोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मोर्चा छत्तीसगढ़ से मोदी मित्र बनाने का एक अभियान भी चलाएगा जिसके तहत मोर्चा कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को मोदी मित्र बनाकर उन्हें भाजपा की वैचारिक अवधारणा से जोड़ेंगे। इसी प्रकार सद्भाव संवाद के जरिए विभिन्न समाजों के मध्य चर्चा के माध्यम से अल्पसंख्यक वर्ग के जैन, सिख व ईसाई समाज सद्भाव कायम कर सभी धर्मों के लोगों को जोड़ा जाएगा।

अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सिद्दीकी ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस जो कहती थी, वही होता था और उसका कोई विरोध नहीं होता था। विरोध में उठने वाले स्वर दबा दिए जाते थे। लेकिन अब भाजपा की राजनीतिक ताकत इतनी बढ़ गई है कि कांग्रेस आज आँख उठाकर भी नहीं देख सकती। जब जनसंघ की शुरुआत हुई थी, तब कितना कठिन दौर रहा होगा, यह सहज ही कल्पना की जा सकती है। श्रद्धेय स्व. डॉ. श्यामाप्रसाद जी मुखर्जी और श्रद्धेय स्व. पं. दीनदयाल जी उपाध्याय ने अनथक परिश्रम करके इसे एक विकल्प के तौर पर खड़ा किया और अब हम सभी कार्यकर्ताओं का यह दायित्व है कि डॉ. मुखर्जी व पं. उपाध्याय ने जिस राजनीतिक वैचारिक संगठन के लिए खून बहाया, उसके लिए हम सब पसीना बहाएँ। श्री सिद्दीकी ने कहा कि प्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बहाने का काम किया था, रोजगार के अवसर बढ़े थे, लेकिन आज कांग्रेस की इस प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में बदहाली और बेरोजगारी के चलते पलायन का दौर फिर से शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 वर्षों के अपने शासनकाल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की अवधारणा को धरातल पर साकार किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रखर नेतृत्व और मजबूत इरादों ने भारत की धाक विश्वमंच पर कायम की है। केंद्र सरकार की योजनाओं का नाम बदलकर उन्हें अपना बताकर छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने केवल झूठा श्रेय बटोरने और पोस्टरबाजी करने काम किया।

अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वरिष्ठ विधायक व पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी तब मदरसों को भरपूर आर्थिक सहायता दी जाती थी लेकिन भूपेश सरकार ने यह बंद कर दिया है। भाजपा और उसकी सरकार ने कभी हिन्दू-मुस्लिम का भेद नहीं किया। अल्पसंख्यक समुदायों को सामुदायिक भवन निर्माण व सामाजिक विकास के लिए भी फण्ड की कमी नहीं आने दी। केन्द्र सरकार ने भी बिना किसी भेदभाव के अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री अहमद ने कहा कि अब समय आ गया है कि चुनाव में कांग्रेस की सरकार से छत्तीसगढ़ को मुक्त किया जाए और इसके लिए अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता तुरंत सक्रिय होकर चुनावी बिगुल फूँक दें।

माल सिद्दीकी अल्पसंख्यकों का नेता नहीं बल्कि बीजेपी का एजेंट है: अनुपम

रायपुर । भाजपा के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष के प्रेस वार्ता पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अनुपम फिलिप कहा कि जमाल सिद्दीक़ी अल्पसंख्यकों के नेता नहीं है। वो बीजेपी आरएसएस के एजेंट है। जमाल सिद्दीकी को हकीकत में अल्पसंख्यक वर्ग की चिंता होती तो वे अब तक भाजपा छोड़ चुके होते? मोदी सरकार बनने के बाद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के लिए मिलने वाले बजट में भारी कटौती किया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग के बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया गया है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अनुपम फिलिप ने कहा कि जमाल सिद्दीक़ी बतायें कि मोदी सरकार ने आखिरी पूर्ण बजट में अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में भारी कटौती आखिर क्यों किया? क्या यह निर्णय अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय नहीं है? 2023-24 के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय को 3,097 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है जबकि 2022-2023 के बजट में यह राशि 5,020 करोड़ रुपये थी। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन बंद करने की साजिश रची गयी है। इसके लिए सिर्फ 10 लाख रुपये का बजट आवंटन इसी बात का संदेह पैदा करता है। नई मंज़िल को भी सिर्फ 10 लाख का बजट दिया गया है। स्किल डेवलपमेंट को भी दस लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। यह राशि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिये नाकाफी है। पिछले साल स्किल डेवलपमेंट का बजट 100 करोड़ रुपये था। यूपीएससी की तैयारी के लिए अल्पसंख्यक छात्रों को मिलनी वाली सुविधाएं बंद कर दी गयी है।भाजपा शासित राज्यों में आज भी अल्पसंख्यक समुदायों के ऊपर हमले हो रहे हैं। उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है। देश से भागने और देश छोड़कर जाने तक की धमकियां दी जाती है।

भूपेश के मंत्री ने ही खोल दी उनकी पोल: अरुण साव

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सांसद अरुण साव ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य में भ्रम फैलाने झूठ का पुलिंदा पेश करते हैं और अब उनके ही पूर्व कृषि मंत्री ने पोल खोल कर रख दी है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि किसानों को मिलने वाला धान का मूल्य केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के दम पर है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए अपने घोषणा पत्र में किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा किया था। लेकिन अब किसानों को इस साल धान की जो कीमत मिलेगी, उसमें 2183 रुपए प्रति क्विंटल केंद्र सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य है। प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा है कि आने वाले पांच साल में धान की कीमत 3600 रुपए प्रति क्विंटल हो जायेगी। वे यह इसलिए बोल रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने 86.5 लाख मीट्रिक टन चावल अर्थात 1 करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का ऐलान किया है। मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के पूरे धान का चावल खरीदेगी। धान का समर्थन मूल्य केंद्र सरकार उत्तरोत्तर बढ़ा रही है। धान का समर्थन मूल्य 2018 से लेकर 2028 तक 10 वर्षों में दो गुना हो जायेगा। इसका मतलब है कि प्रदेश में किसानों को धान का बढ़ता मूल्य केंद्र की भाजपा सरकार के कारण मिल रहा है। लेकिन भूपेश सरकार जो बोनस दे रही है, वह तो एक धेला भी नहीं बढ़ा है। बल्कि किसान जब 20 क्विंटल धान बेचेंगे तो प्रति क्विंटल बोनस भी कम हो जायेगा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री साव ने कहा कि किसानों के कल्याण की बात केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। प्रदेश निर्माण से अब तक भाजपा ने ही किसानों के धान खरीदने और बोनस देने की शुरुआत की। आने वाले समय में भी मोदी सरकार के इंजन से प्रदेश में भाजपा सरकार का इंजन मिलेगा तो डबल इंजन सरकार किसानों के आर्थिक कल्याण के लिए निर्णय लेगी। ऐसा प्रदेश में अन्य विकास को रोककर नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के निर्माण से लेकर सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल भवन, अस्पताल भवनों के निर्माण तक समस्त क्षेत्र में ध्यान देगी।

परिवर्तन यात्रा 12 से 14 को रायगढ़ आएंगे पीएम मोदी

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से शुरु होगी और इस परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। वहीं 16 सितंबर को जशपुरनगर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को रायगढ़ के कोड़ाराई में आयोजित परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे जहां वे जनसभा को संबोधित करेंगे। परिवर्तन यात्रा का समापन बिलासपुर में होगा जिसमें भी प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे।

अब लोग दोबारा धोखा नहीं खाएंगे: बृजमोहन

रायपुर। पूर्व मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीतने अपने जन घोषणापत्र में 36 वादे किए थे, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अब कांग्रेस फिर से जनता को ठगने की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस समझ ले कि एक बार उन्होंने लोगों को धोखा दे दिया, अब लोग दोबारा धोखा खाने वाले नहीं है। बृजमोहन ने कहा कि हमारे मुंह में राम, अल्लाह और ईसा मसीह है, क्योंकि भगवान एक है। इसको मुस्लिम अल्लाह के नाम से पुकारते हैं, हिन्दू राम के नाम से पुकारते हैं, और ईसाई यीशु के नाम से पुकारते हैं। बृजमोहन ने कहा कि कांग्रेस ने लोगों को बांटने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो सनातन है, वो हिंदू है। कांग्रेस की जो बांटने की रणनीति है, उसे मुस्लिम धीरे-धीरे समझने लगे हैं, कि उसे कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक बनाया है, इसलिए यूपी, बिहार से कांग्रेस साफ हो गई। अब पूरे देश से साफ होने वाली है। बृजमोहन ने कहा कि भारत को तोड़ने वाले, भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं। जिन्होंने भारत के दो हिस्से किए, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में बांट दिया। आज वे भारत जोडो की बात कर रहा है। वो भारत जोड़ने नहीं, कांग्रेस पार्टी जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं।

कांग्रेस की 35 सीट पर एक 12 पर दो नाम तय: चौबे

■ टिकट के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं

रायपुर। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए चली मैराथन बैठक के बाद 35 सीट पर एक नाम तय हो गया है। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष डा चरणदास महंत और विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम का नाम प्रमुख है।

इसके साथ ही 12 सीटों पर दो नाम का पैनल बनाया गया है। इसमें दो मंत्री और दस विधायकों की सीट शामिल हैं। मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया से चर्चा में कहा कि इसी सप्ताह कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी होगी। आठ सितंबर को स्क्रीनिंग कमेटी में नाम पर चर्चा होगी। आधे से अधिक सीटों पर चर्चा पूरी हो चुकी है। अधिकांश सीटों पर सिंगल नाम है, कुछ सीटों पर दो नाम का पैनल तैयार है। कांग्रेस की सूची केंद्रीय चुनाव समिति जारी करेगी।

रविंद्र चौबे ने कहा कि टिकट के लिए किसी को भी दिल्ली जाने की आवश्कता नहीं है। कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई है। ब्लाक कमेटी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित सभी ने आवदेन दिया है। ब्लाक कांग्रेस के पास 2900 से अधिक आवेदन आए थे।उसकी समीक्षा के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चुनाव समिति को सौंपा है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक राज्य में होगी, इसलिए दिल्ली दौड़ लगाने की कोई जरूरत नहीं है।

7 सितंबर को रायपुर पहुंचेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के छत्तीसगढ़ दौरे पर रविंद्र चौबे ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की आठ सितंबर को राजनांदगांव में विशाल जनसभा है। इसी परिपेक्ष्य में गुरुवार को मल्लिकार्जुन खरगे रायपुर आ रहे हैं। यहां कांग्रेस के बड़े नेताओं, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, और मंत्रियों से चर्चा करेंगे। चुनाव का समय आ गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्गदर्शन में हम सबको मिलेगा।

छत्तीसगढ़/राजधानी — प्रमुख समाचार

कहां-कहां से इंडिया हटायेंगे मोदी?: बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि इंडिया गठबंधन से मोदी और भाजपा इतने भयभीत हो चुके हैं कि देश का ही नाम बदलने की सोच रहे हैं। अंग्रेजों की मुखबिरी करने और ?60 पेंशन पाने वाले लोग आज इंडिया शब्द को गुलामी का प्रतीक बता रहे हैं।एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने में 14304 करोड़ का अनुमानित खर्च आ सकता है। राजनैतिक दुर्भावना के कारण इतनी बड़ी राशि का अपव्यय भाजपा कि गिरी हुई मानसिकता को दर्शाता है।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि अगर इंडिया नाम में बदलाव किया जाता है तो कई संस्थानों और संगठनों का नाम बदलना पड़ेगा। अगर नाम में बदलाव हुआ तो एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया, इंडियन रेल्वे, आल इंडिया रेडियो, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी आदि सभी के नाम से इंडिया हटाना पड़ेगा और यहां तक की भारतीय करेंसी पर से भी इंडिया शब्द हटाना पड़ेगा जिसके लिये फिर से एक बार नोटबंदी करनी होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा खुद इंडिया शाइनिंग, मेक इन इंडिया जैसे नारे दिए हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी उसमें ही बदलाव करेगी ?देश की जनता गर्व से कहती है कि आई लव माय इंडिया क्या मोदी भारतीय जनता के दिल में बसे इंडिया को हटा सकेंगे।

भूपेश राहुल छत्तीसगढ़ की परंपरा के अनुरूप प्रायश्चित करें: चंद्राकर

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, पूर्व मंत्री व विधायक अजय चंद्राकर ने कहा है कि गौ हत्या के पापी भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की संस्कृति और वैदिक परंपरा के अनुसार प्रायश्चित करने विधिवत रूप से 21 दिनों तक भिक्षा मांग कर उससे प्राप्त पैसों से पाटन विधानसभा के ग्राम बानबरद स्थित भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा करें और स्वयं को गौ हत्या के पाप से मुक्ति दिलाएं। भूपेश बघेल के साथ-साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी समान रूप से गौ हत्या के पापी हैं तो भूपेश बघेल उन्हें भी अपने साथ भिक्षा मांगने के लिए ले जाएं। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 2 सितंबर को नया रायपुर में आयोजित राजीव मितान सम्मेलन के बाद फेंके गए खाने का सेवन करने से करीब 45 गायों की मृत्यु हुई है। जिसके लिए सीधे तौर पर इस आयोजन के यजमान भूपेश बघेल और मुख्य अतिथि राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। चुनाव के पहले जनता के पैसे पर जो आयोजन किया गया, उसमें माता अन्नपूर्णा का भी अपमान किया गया है। जिस बड़े पैमाने पर भोजन फेंका गया, वह जनता का पैसा ही है। जिसे कांग्रेस ने इस तरह फेंका है कि आधा सैकड़ा के करीब गौ माता परलोक सिधार गईं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति के नाम पर स्वांग करने वाले भूपेश बघेल के कृत्य से छत्तीसगढ़ राज्य भी अभिशप्त हुआ है क्योंकि राजा के कृत्य का परिणाम राज्य को भी भुगतना पड़ता है। यदि भूपेश गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए संस्कृति के अनुरूप प्रायश्चित नहीं करते हैं।

भाजपा के नेता गौ माता के अनुदान खा गए थे: धनंजय

रायपुर । पूर्व मंत्री विधायक एवं भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पूरा प्रदेश ने देखा है जिस सरकार में अजय चंद्राकर मंत्री थे उस सरकार में भाजपा नेताओं के द्वारा संचालित गौशाला में गौ माता की निर्मम हत्या होती थी। गौ माता के हाड़ और मांस को भाजपा नेता मछलियों को खिलाया करते थे। गौ माता के नाम से अनुदान लेकर भाजपा के नेता खाते पीते थे। सरकारी जमीन पर कब्ज़ा करते थे। भाजपा को गौ माता का श्राप लगा है भाजपा ने गौ माता के साथ धोखा किया है जिसका ही परिणाम है कि भाजपा 15 साल के सत्ता के बाद 15 सीट में सिमट गई।प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा चुनावी गौ सेवक है चुनाव में भोले भाले गौ सेवकों का वोट लेने के लिए गौ माता की जयकारा लगाती है और सत्ता मिलने के बाद गौ माता के नाम से मिलने वाले अनुदान को खाती है। रमन सरकार के समय आरएसएस और भाजपा नेताओं द्वारा संचालित गौशालाओं में गौवंश पशुधन की निर्मम हत्यायें होती थी। गौ माता के नाम पर मिलने वाले अनुदान से आरएसएस और भाजपा के नेता पलते थे और गौ माताएं मार दी जाती थी। दुर्ग जिले के धमधा के राजपुर की गौशाला में गायें चारे-पानी के अभाव में मारी गई थी।

प्रदेश सरकार को शर्म से गड़ जाना चाहिए : रंजना

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रंजना साहू ने जशपुर जिले में ऐन शिक्षक दिवस के दिन एक आदिवासी शिक्षिका के साथ हुए गैंग रेप की घटना को लेकर प्रदेश सरकार पर करारा हमला बोला है। श्रीमती साहू ने जशपुर जिले के दनगरी वाटर फॉल घूमने गई निजी स्कूल की एक शिक्षिका के साथ दो लोगों द्वारा बलात्कार की वारदात को अंजाम दिए जाने का मामला सामने आने पर कहा कि प्रदेश सरकार को अब तो शर्म से गड़ जाना चाहिए कि उसके तमाम दावों की धज्जियाँ उड़ाते दरिंदे लगातार गैंग रेप करके महिलाओं की अस्मिता को लहूलुहान कर रहे हैं। इससे प्रदेश सरकार के महिला और आदिवासी विरोधी चरित्र बेनकाब हो गया है। महिला सुरक्षा के मामले में कांग्रेस की प्रदेश सरकार फिसड्डी साबित हुई है और सरकार महिलाओं की सुरक्षा करने में नाकारा साबित है। शिक्षक दिवस के दिन आदिवासी शिक्षिका के साथ दुराचार शर्मसार करता है। सरकार आंखो पर पट्टी बांधकर और कानों में रुई ठूँसकर बैठी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इस घटना पर कोई बयान नहीं आएगा, क्योंकि दुराचारी युवा कांग्रेस का नेता है। श्रीमती साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी की बेटियों के साथ रोज ऐसी वारदातें घट रही हैं, जिससे प्रदेश शर्मसार हो रहा है। प्रदेश सरकार की पहली जिम्मेदारी और प्राथमिकता यहाँ की बेटियाँ और उनकी सुरक्षा है। चूँकि प्रदेश की भूपेश सरकार प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा करने में नाकारा साबित हुई है।

दुराचारियों और दुष्कर्मियों को प्रश्रय दे रही है कांग्रेस: गोमती

रायपुर। नगर जशपुर जिले मे आदिवासी महिला शिक्षक से सामूहिक दुष्कर्म की घटना की सांसद श्रीमती गोमती साय और जिला पंचायत जशपुर की अध्यक्ष श्रीमती रायमुनि भगत ने कड़े शब्दों मे निंदा की है. सांसद श्रीमती साय ने कहा की छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार महिलाओ की मान सम्मान की रक्षा करने मे पूरी तरह से विफल साबित हुई है. शांति का टापू कहलाने वाले जशपुर जिले मे बीते पांच साल के दौरान दुष्कर्म सहित महिला हिंसा की घटनाओ की बाढ़ आ गई है. कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है. लेकिन कांग्रेस सरकार के जिम्मेदार मंत्री इस मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं. सांसद ने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर, सलाखों के पीछे भेजने की मांग की है. जिला पंचायत जशपुर की अध्यक्ष श्रीमती रायमुनी भगत ने घटना की निंदा करते हुए कहा की कांग्रेस सरकार में महिलाओं की सुरक्षा की आशा करना ही बेकार है. जिस सरकार के जिम्मेदार अधिकारी और मंत्री दिव्यांग बच्चियों से दुष्कर्म के अमानवीय मामले में मौन साध सकते हैं, वे सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं. महिलाओ के साथ हो रहे इस अन्याय और तमाशबिन बने कांग्रेसियो को अब, छत्तीसगढ़ की जनता जवाब देगी. श्रीमती रायमुनि भगत ने कहा कि दनगरी में हुए सामूहिक दुष्कर्म का आरोपित सद्दाम खान युवक कांग्रेस का पूर्व सचिव और सोशल मीडिया प्रभारी भी रह चुका है।

कृषि विवि ने अलसी की 17 उन्नत किस्में विकसित कीं : डॉ. चंदेल

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद एवं इंडियन सोसायटी ऑफ आइलसीड रिसर्च, हैदराबाद के संयुक्त तत्वावधान में अखिल भारतीय समन्वित कृषि अनुसंधान परियोजना अलसी एवं कुसुम पर दो दिवसीय वार्षिक कार्यशाला का आज यहां समापन हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल थे। समापन समारोह की अध्यक्षता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सहायक महानिदेशक (दलहन एवं तिलहन) डॉ. संजीव गुप्ता ने की। समापन समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. चंदेल ने कहा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में अलसी एवं कुसुम

परियोजना के तहत काफी अच्छा कार्य किया गया है। परियोजना के अंतर्गत अलसी की 17 नवीन उन्नत प्रजातियां तथा कुसुम की 3 नवीन उन्नत प्रजातियां विकसित की गई है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। डॉ. चंदेल ने आशा व्यक्ति की कि इस दो दिवसीय वार्षिक कार्यशाला के दौरान किये गए विचार-मंथन के सार्थक परिणाम प्राप्त होंगे और इनसे भविष्य के अनुसंधान की रूप-रेखा तय की जा सकेगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेश डॉ. संजीव गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि अलसी और कुसुम फसलों पर आयोजित इस दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान परियोजना के तहत विगत वर्षों में किये गये कार्यों तथा उपलब्धियों की समीक्षा की गई तथा आगामी वर्ष के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है। उन्होंने कार्यशाला के सफल आयोजन के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति तथा समस्त वैज्ञानिकों के प्रति आभार व्यक्त किया। डॉ. गुप्ता इन दोनों फसलों के अन्तर्गत इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किये जा रहे अनुसंधान कार्यों की सराहना भी की। इस अवसर पर दलहनी एवं तिलहनी फसलों के अनुसंधान कार्य में विशिष्ट योगदान देने वाले कृषि वैज्ञानिकों को सम्मानित भी किया गया। कार्यशाला में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में अलसी के रेशे से लिनन कपडा निर्माण की प्रौद्योगिकी को भी प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. आर.के. माथुर, आई.सी.ए.आर.-एन.बी.ए.आई.आर. के निदेशक डॉ. सुशील, एन.आई.बी.एस.एम. बरौंडा के निदेशक डॉ. पी.के. घोष, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संचालक अनुसंधान तथा कार्यशाला समन्वयक डॉ. विवेक कुमार त्रिपाठी तथा सह-समन्वयक डॉ. नंदन मेहता, डॉ. राजीव श्रीवास्तव, डॉ. संजय द्विवेदी एवं बी.पी. कतलम भी उपस्थित थे।

बिजली कर्मियों को जागरूक करने दो लघु फिल्मों का एमडी ने किया विमोचन

रायपुर। प्रबंध निदेशक श्री मनोज खरे ने मैदानी विद्युत कर्मियों को सुरक्षा एवं सतर्कता हेतु जागरूक करने के उद्देश्य से दो लघु फिल्मों का विमोचन किया है। सेवा भवन में अपने कार्यालय कक्ष में एक सादे समारोह में उन्होंने दोनों ही फिल्मों का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने उम्मीद जताई कि फिल्म मैदानी अमले को कार्य के दौरान बाखबर रहकर काम के लिए प्रेरित करेगी। उन्हें हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि उनके घर पर उनका कोई अपना इंतजार कर रहा है। श्री खरे ने कहा कि कार्य के दौरान छोटी ङ्क छोटी सावधानियाँ कई बड़ी दुर्घटनाओं से बचाती है। विमोचन अवसर पर कार्यपालक निदेशक श्री भीम सिंह कंवर,श्री आर.ए. पाठक, अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री एस.आर.बी.खंडेलवाल, श्री के.एस.भारती,श्री एम.डी. बड़गैय्या प्रमुख रूप से उपस्थित थे। ई.डी. श्री कंवर ने बताया कि थैंक्यू पापा शीर्षक से बने लघु फिल्मों को मैदानी कर्मचारियों विशेषकर लाइन स्टॉफ को दिखाया जा रहा है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.